Website : www.kalamlok.com

वर्ष - 10 अंक - 136

बक्सर, गुरूवार 17 सितम्बर 2026

कलम लोक

₹7 | पृष्ठ - 8 | मूल्य 2 रू.

“ बड़प्पन बड़े आदमियों के संपर्क से नहीं, अपने गुण, कर्म और स्वभाव की निर्मलता से मिला करता है।

यूपीआई चार्ज वापस लेने का सवाल ही नहीं, सरकार की दो टूक; विदेशी दबाव के आरोप भी खारिज

नई दिल्ली (एजेंसी)। सरकार की तरफ से ऑनलाइन पेमेंट यूपीआई से 2000 से ज्यादा के व्यापारिक ट्रांजैक्शन पर लगाए गए चार्ज ने विरोध बढ़ा दिया है। कांग्रेस पार्टी समेत विपक्षी नेताओं ने इसे वापस लेने की अपील की है। वहीं, इस मामले पर बुधवार को एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस फैसले को वापस नहीं लिया जाएगा। 15 अक्तूबर से नए नियम लागू होंगे।

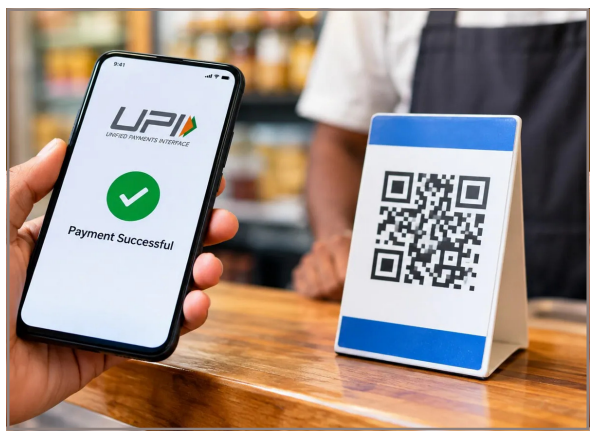

बता दें, सरकार की तरफ से सूचना जारी करके बताया गया था कि 15 अक्तूबर से भारत का लोकप्रिय डिजिटल पेमेंट सिस्टम UPI फ्री नहीं रहेगा। हालांकि, पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन पर कोई फीस नहीं ली जाएगी। लेकिन 2000 से अधिक रूपए के मर्चेंट पेमेंट पर 0.40 प्रतिशत का मर्चेंज डिस्काउंट रेट लागू होगा। सरकार के इस फैसले के बाद इसका विरोध चालू हो गया। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर सीधा हमला करते हुए कहा कि उन्होंने विदेशी दबाव में आकर यह फैसला लिया है। उन्होंने अपील की इस फैसले को वापस ले लिया जाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया। इसमें लिखा, 'एक बार इंदिरा जी से पूछा गया ता कि उनका झुकाव लेफ्ट की तरफ है या राइट की तरफ? इस पर उन्होंने कहा था कि 'मैं ने लेफ्ट की तरफ झुकती हूं और न ही राइट की तरफ, मैं सीधी खड़ी रहती हूं।' लेकिन मोदी जी की विचार इससे बिल्कुल अलग हैं।'

यूपीआई टैक्स वापस लीजिए- राहुल गांधी

कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा, 'पीएम मोदी न लेफ्ट की तरफ है और न ही राइट की तरफ हैं। वह तो सीधे डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुकने का फैसला कर चुके हैं। यूपीआई पर टैक्स लगाकर और अमेरिका को बड़ी रकम देकर उन्होंने हर भारतीय के ऊपर टैक्स का बोझ डाल दिया है। मोदी जी, कृपया अमेरिका के सामने झुकना बंद कीजिए और रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए, खड़े हो जाइए और यूपीआई टैक्स को वापस ले लीजिए।'

राहुल गांधी समेत विपक्ष के तमाम नेताओं की तरफ से विदेशी दबाव में फैसला लेने के आरोपों को सरकार की तरफ से खारिज कर दिया गया है। सरकार की तरफ से कहा गया कि यह फैसला यूपीआई को ध्यान में रखकर ही लिया गया है। 96 फीसदी से ज्यादा ट्रांजेक्शन 2000 रुपए से कम में ही होते हैं। इसके अलावा पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन पर भी कोई चार्ज नहीं वसूला जाएगा। हालांकि, इसके बाद भी विपक्ष लगातार हमलावर बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी समेत देश भर के विपक्षी नेताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। कई जगहों पर इस फैसले के विरोध में दुकानदारों ने क्यूआर कोड हटाने भी शुरू कर दिए हैं।

झीरम घाटी में 29 लोगों की हत्या मामले में बड़ा फैसला, सभी दोषियों को फांसी की सजा

रायपुर (एजेंसी)। साल 2013 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की 'परिवर्तन यात्रा' पर हुए झीरम घाटी माओवादी हमले के मामले में NIA की विशेष अदालत ने सभी 10 दोषियों को मौत की सजा सुनाई है। यह फैसला बस्तर जिले की नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी की स्पेशल कोर्ट ने सुनाया। इस हमले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं समेत 29 लोगों की मौत हो गई थी।

कोर्ट के फैसले की जानकारी देते हुए एजेंसी के एक वकील बताया कि झीरम घाटी हमला मामले में जगदलपुर में NIA की विशेष अदालत ने 5 सितंबर को दो महिलाओं समेत सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया था और सजा पर 16 सितंबर तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। उन्होंने बताया कि अदालत ने आज सभी 10 दोषियों को मौत की सजा सुना दी। जिन दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई है उनकी पहचान प्रमिला मोदियाम (40), चैतू लेकाम, सुमित्रा पुनेम मोदियाम, मुक्का मंडावी, कोसा कवासी, आयता मरकाम, मडकामी देवा, जोगा मडकामी, बंजामी सन्ना और महादेव नाग के रूप में हुई है।

हमले के 13 साल बाद आया कोर्ट का फैसला

इन सभी माओवादियों ने बस्तर जिले के दरभा थानाक्षेत्र की झीरम घाटी में 25 मई 2013 को नेशनल हाईवे से गुजर रही कांग्रेस की 'परिवर्तन यात्रा' पर घात लगाकर हमला किया था। इस हमले में कई कांग्रेस नेताओं, आम नागरिकों और 10 सुरक्षाकर्मियों समेत कम से कम 29 लोग मारे गए थे तथा 30 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।

मृतकों में तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार पटेल और उनके बेटे दिनेश, विपक्ष के पूर्व नेता महेंद्र कर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्या चरण शुक्ल और वरिष्ठ नेता तथा पूर्व विधायक उदय मुदलियार शामिल थे।

यह 'परिवर्तन रैली' उस साल के अंत में होने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रचार के लिए आयोजित की गई थी। घटना के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज किया था, लेकिन रमन सिंह के नेतृत्व वाली तत्कालीन भाजपा सरकार ने हमले के दो दिन के भीतर ही जांच हद्ध को सौंप दी थी। राज्य सरकार ने इस घटना की जांच के लिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग भी बनाया था।

दिशा सालियान से कभी मिला तक नहीं...

एफआईआर में आया नाम तो आदित्य ठाकरे ने तोड़ी चुप्पी

मुंबई (एजेंसी)। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने बुधवार को दावा किया कि वह दिवंगत अभिनेत्री दिशा सालियान को नहीं जानते थे और न ही दिशा से कभी उनकी मुलाकात हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग राजनीतिक मंशा से उनका नाम इस मामले से जोड़कर उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे का यह बयान सीबीआई द्वारा 2020 के दिशा सालियान मौत मामले में प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद आया है।

दरअसल, मुंबई उच्च न्यायालय के निर्देश और दिशा के पिता की ओर से दायर याचिका के अनुपालन में दर्ज प्राथमिकी में किसी आरोपी का नाम नहीं है। शिवसेना के विधायक ने कहा कि राजनीतिक मंशा से किया जा रहा ऐसा दुष्प्रचार उन्हें सच्चाई के लिए लड़ने से नहीं रोक पाएगा।

आदित्य ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि आइये एक बार फिर शोर से अलग होकर तथ्यों की बात करें। मैं दिशा सालियान से कभी नहीं मिला और न ही उन्हें जानता था। करीब छह वर्षों से कुछ लोग राजनीतिक और निजी मंशा के साथ लगातार इस दुखद मामले से मेरा नाम जोड़ रहे हैं। यह बिना किसी सबूत के चरित्र हनन की जानबूझकर की गई कोशिश है। उन्होंने कहा कि निहित स्वार्थ वाले लोग बिना किसी सबूत के लगातार मुझे बदनाम करने का अभियान चला रहे हैं और यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर उन कुछ लोगों से, जो सोचते हैं कि राजनीतिक फायदे के लिए किए जा रहे ऐसे दुर्भावनापूर्ण प्रयास हमें सच्चाई और अपने साथी नागरिकों के लिए लड़ने से रोक देंगे, कहना चाहता हूं कि उनकी यह रणनीति विफल है।

आठ जून 2020 को सालियान की हुई थी मौत

बता दें कि सालियान (28) की आठ जून 2020 को मुंबई के मलाड इलाके में एक आवासीय इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। मुंबई पुलिस ने दुर्घटनावश मौत की रिपोर्ट दर्ज की थी और बाद में जांच के बाद इसे आत्महत्या का मामला बताया था। इसके एक सप्ताह बाद 14 जून 2020 को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत बांद्रा स्थित अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे, जिसके बाद दोनों मौतों के बीच संभावित संबंध को लेकर अटकलें लगाई गई थीं। दो सितंबर को मुंबई उच्च न्यायालय ने सालियान की मौत की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। अदालत ने छह साल तक प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को लेकर मुंबई पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा था कि मामले की जांच जवाबों से अधिक सवाल खड़े करती है।

महुआ मोइत्रा को दिखाए गए काले झंडे, गाड़ी पर फेंके गए अंडे

कोलकाता (एजेंसी)। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में विरोध का सामना करना पड़ा। वह अपने संसदीय क्षेत्र में एक बैठक में शामिल होने पहुंची थीं। इसी दौरान कुछ लोगों ने उन्हें घेरकर नारेबाजी की और काले झंडे दिखाए। उनकी गाड़ी पर अंडे भी फेंके गए। पुलिस ने मौके से उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। महुआ मोइत्रा ने इस घटना के पीछे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हाथ होने का आरोप लगाया है।

घटना के बाद महुआ मोइत्रा ने एक वीडियो जारी कर कहा कि वह अपने संसदीय क्षेत्र में बैठक के लिए पहुंची थीं। उनके अनुसार, इसी दौरान भाजपा के मंडल सभापति, पंचायत समिति सभापति और अन्य कार्यकर्ता वहां पहुंचे। महुआ ने दावा किया कि उनके साथ पुलिसकर्मी मौजूद थे और पुलिस की मौजूदगी में ही उनके ऊपर अंडे फेंके गए।

सोना खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर!

अब 67% ज्यादा देनी पड़ेगी ये फीस; 5% तक लुढ़के गोल्ड स्टॉक्स

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय ज्वेलरी कंपनियों के शेयरों में बुधवार, 16 सितंबर को अचानक गिरावट देखने को मिली। इसकी बड़ी वजह सोने की ज्वेलरी पर लगने वाली हॉलमार्किंग फीस में बढ़ोतरी को माना जा रहा है। BIS (Bureau of Indian Standards) ने गोल्ड आर्टिकल की हॉलमार्किंग फीस ?45 से बढ़ाकर 75 रू. प्रति आर्टिकल कर दी है, यानी फीस में करीब 67% का इजाफा हुआ है। इस खबर के बाद कल्याण ज्वैलर्स इंडिया (Kalyan Jewellers India) और PC Jeweller के शेयरों में करीब 4-5% तक की गिरावट आई, जबकि हाल ही में लिस्ट हुई ललिता ज्वैलरी मार्ट (Lalithaa Jewellery Mart) के शेयर 5% के लोअर सर्किट पर पहुंच गए।

हॉलमार्किंग का क्या मकसद?

हॉलमार्किंग का मकसद ज्वेलरी में इस्तेमाल होने वाले कीमती धातु की शुद्धता की पुष्टि करना है। BIS हॉलमार्क वाली ज्वेलरी पर आम तौर पर BIS का लोगो, कैरेट या मिलेसिमल फाइननेस और 6 अंकों का HUID नंबर होता है। ऐसे में हॉलमार्किंग ग्राहक को ज्वेलरी की शुद्धता से जुड़ी जानकारी देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि, फीस बढ़ने से ज्वेलर्स की अनिवार्य अनुपालन लागत बढ़ सकती है और इसी वजह से बाजार में इसे लेकर चिंता दिखाई दे रही है।

गोल्ड ज्वेलरी के नए नियमों में बदलाव

BIS का यह नया शुल्क 14 सितंबर 2026 को जारी BIS (Hallmarking) संशोधन नियम, 2026 के तहत लागू किया गया है। नए नियमों के मुताबिक गोल्ड ज्वेलरी के लिए 75 रू. प्रति आर्टिकल हॉलमार्किंग फीस देनी होगी। इसके साथ ही एक कंसाइनमेंट के लिए न्यूनतम शुल्क 200 रू. रखा गया है। वहीं, सिल्वर आर्टिकल की हॉलमार्किंग फीस में बदलाव नहीं किया गया है। चांदी के लिए शुल्क 35 रू. प्रति आर्टिकल रहेगा और एक कंसाइनमेंट पर कम से कम 150 रू. का भुगतान करना होगा।

इस मंदिर में जाने वाले भक्तों को मिलेगा बीमा कवर

तिरूपति (एजेंसी)। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने बताया कि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम् अब एलआईसी के साथ मिलकर हर श्रद्धालु को बीमा देगा। मंदिर दर्शन के दौरान अगर किसी की मौत हो जाती है, तो परिवार को 2 लाख रुपये दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि टीटीडी ने आधार से जुड़ा ऑनलाइन बीमा शुरू करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि टीटीडी ने एलआईसी के साथ मिलकर हर भक्त को बीमा देने का फैसला लिया है। मौत होने पर इस बीमा से 2 लाख रुपये मिलेंगे। सीएम नायडू ने आगे कहा कि भगवान वेंकटेश्वर की महिमा, तिरुमला का इतिहास, पौराणिक आख्यानों और भगवान के दिव्य विवाह को प्रदर्शित करने के लिए श्री वेंकटेश्वर संग्रहालय का आधुनिकीकरण कर इसे फिर से खोल दिया गया है।

भारत ने मक्का पर कथित ड्रोन हमले की निंदा की

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत ने सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का पर कथित ड्रोन दागे जाने की घटना पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत नागरिकों के जीवन और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली किसी भी कार्रवाई का विरोध करता है। उन्होंने कहा कि मक्का के पास हुई यह घटना विशेष रूप से चिंताजनक है क्योंकि यह शहर दुनिया भर के मुसलमानों के लिए विशेष महत्व रखता है।

जायसवाल ने कहा, हम मक्का के पास हुए ड्रोन हमले से बेहद चिंतित हैं। भारत सऊदी अरब की संप्रभु भूमि पर होने वाले हमलों और नागरिकों के जीवन और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करता है।

वंदे मातरम पर इस राज्य में विवाद गहराया; गृह मंत्री बोले– दे दूंगा इस्तीफा, अगर विपक्षी नेताओं ने...

बेंगलुरु (एजेंसी)। कर्नाटक के गृह मंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे प्रियांक खरगे ने सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम को केवल दो छंदों तक सीमित करने के राज्य सरकार के फैसले का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि कहा कि यह फैसला महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और रवींद्रनाथ टैगोर जैसी प्रमुख राष्ट्रीय हस्तियों के निर्णय के अनुरूप है। प्रियांक ने इस मामले में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी निशाना साधा और कहा कि उनकी पार्टी (कांग्रेस) और (राज्य की कांग्रेस) सरकार को उनसे कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। दरअसल, कर्नाटक सरकार के इस फैसले ने राष्ट्रीय गीत के सभी छंदों को गाने की BJP की मांग वाले विवाद को और बढ़ा दिया है।

भीड़ को संबोधित करते हुए खरगे ने इसके साथ ही कर्नाटक BJP के दो बड़े नेताओं बी.वाई. विजयेंद्र और आर. अशोक को चुनौती दी कि वे 'बिना टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल किए या कागज में देखे' वंदे मातरम के सभी छंद गाकर दिखाएं। खरगे ने कहा, '...अगर वे ऐसा कर पाए, तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा।' कांग्रेस नेता ने इस विवाद को लेकर BJP और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। खरगे ने इसके साथ ही सवाल किया, 'हमारे पूर्वजों ने तय किया था कि वंदे मातरम के केवल दो छंद ही गाए जाएंगे। अब BJP और PM मोदी सभी छंद गाना चाहते हैं। क्या वे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर से भी बड़े हैं?' उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ''क्या हमें उन लोगों से देशभक्ति का पाठ सीखने की जरूरत है, जिन्होंने अंग्रेजों से 60 रुपये की पेंशन ली थी? देश की आजादी में उनका क्या योगदान है? हमारा फैसला उन लोगों के फैसले के मुताबिक है, जिन्होंने इस देश के लिए लड़ाई लड़ी और अपनी जान दी। हमें भाजपा या आरएसएस से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है।'' कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने आदेश दिया है कि उसके कार्यक्रमों में वंदे मातरम् के केवल पहले दो अंतरों का ही गायन किया जाए, सिवाय उन कार्यक्रमों के जिनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल शामिल हों।

छह साल की भतीजी से रेप व हत्या करने वाले को मौत की सजा, अदालत ने मामले को 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' माना

दुर्ग (एजेंसी)। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की एक अदालत ने छह साल की बच्ची से दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या करने के मामले में आरोपी को मौत की सजा सुनाई है। विशेष पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण) फास्ट ट्रैक अदालत ने वारदात के 24 वर्षीय आरोपी को इस केस में दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई। आरोपी ने अपनी भतीजी के साथ इस वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद अदालत ने उसके अपराध को 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' श्रेणी का माना। न्यायालय ने पीड़ित परिवार को राज्य शासन की आहत प्रतिकर योजना के तहत सात लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने का भी निर्देश दिया है।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ फास्ट ट्रैक कोर्ट एवं विशेष पॉक्सो न्यायालय दुर्ग ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने पॉक्सो अधिनियम की धारा 6(1) तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) के तहत दोषी को मृत्युदंड और दोनों धाराओं में 5-5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही बीएनएस की धारा 238(क) के तहत उसे 5 वर्ष के सश्रम कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदंड की सजा भी सुनाई। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। मृत्युदंड की पुष्टि के लिए मामला नियमानुसार छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के समक्ष जाएगा।

मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि पिछले साल छह अप्रैल को उसे 6 साल 3 महीने उम्र की बच्ची के लापता होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद मोहन नगर थाने में अपराध क्रमांक 133/2025 दर्ज कर तलाश शुरू की गई। बच्ची बाद में एक वाहन में पड़ी मिली थी, जिसे अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। पोस्टमार्टम से बच्ची का यौन उत्पीड़न होने का पता चला था। मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच दल गठित किया गया था।

पाकिस्तानी जहाज की भारतीय नौसेना पोत से हुई टक्कर, भारत ने राजनयिक को तलब किया

नई दिल्ली (एजेंसी)। अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में पाकिस्तान की नौसेना के एक जहाज और भारतीय नौसेना के एक पोत के बीच टक्कर होने के बाद भारत ने बड़ा कदम उठाया है। भारत ने विरोध दर्ज कराने के लिए दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के प्रभारी को तलब कर समुद्र में पाकिस्तानी नौसेना इकाइयों के अस्वीकार्य और गैर-पेशेवर आचरण को उजागर किया, जिसके कारण यह टक्कर हुई। हालांकि, इस घटना में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। विदेश मंत्रालय ने कहा, नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के चार्ज डी अफेयर्स को विदेश मंत्रालय में बुलाया गया। उनसे समुद्र में पाकिस्तानी नौसेना की इकाइयों के उस अस्वीकार्य और गैर-पेशेवर व्यवहार पर कड़ा विरोध जताया गया, जिसके कारण भारतीय नौसेना की एक इकाई के साथ टक्कर हुई। उनसे कहा गया कि वे संबंधित पाकिस्तानी अधिकारियों तक यह बात पहुंचाएं कि ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतनी चाहिए।

अन्नपूर्णा योजना: पीएम मोदी के जन्मदिन पर 3000 रु. का तोहफा, इन महिलाओं के खाते में आएंगे पैसे

कोलकाता (एजेंसी)। 17 सितंबर यानी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। इस मौके पर पश्चिम बंगाल सरकार अन्नपूर्णा दिवस के रूप में मना रही और राज्य की अन्नपूर्णा योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खाते में 3000 रुपये की मासिक सहायता भेजने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के अनुसार, इस महीने करीब 1.58 करोड़ महिलाओं को यह राशि मिल सकती है, जो अगस्त से लगभग 10 लाख ज्यादा है। अब सवाल यह है कि यह पैसा किन महिलाओं के खाते में आएगा और नए नियमों के बाद कौन पात्र माना जाएगा।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने एक बंगाली अखबार से बात करते हुए बताया कि सितंबर महीने में करीब 1.58 करोड़ महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। यह संख्या अगस्त की तुलना में लगभग 10 लाख अधिक है। योजना शुरू होने के बाद लाभार्थियों की संख्या लगातार बढ़ी है। जून में करीब 28 लाख महिलाओं को पैसा मिला। जुलाई में यह आंकड़ा तेजी से बढ़कर 1.19 करोड़ हो गया। सितंबर में करीब 10 लाख और महिलाओं के शामिल होने से कुल संख्या 1.58 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री का दावा है कि आवेदन की जांच और सत्यापन के बाद सही पात्र महिलाओं को सूची में जोड़ा जा रहा है। इसी वजह से हर महीने लाभार्थियों की संख्या बढ़ रही है। अगस्त में मुख्यमंत्री ने योजना के नए नियम बताए थे। जिन महिलाओं की मासिक कमाई 10000 रुपये से ज्यादा है, उन्हें पैसा नहीं मिलेगा। इसके अलावा जिन परिवारों की सालाना आय 12 लाख रुपये से ज्यादा है, वे भी पात्र नहीं हैं। विकलांगता पेंशन या पीएम-किसान जैसी कुछ सरकारी मदद पहले से लेने वाली महिलाएं, बाकी शर्तें पूरी करने पर योजना में रह सकती हैं। गांव की महिलाओं के लिए घर में तीन से ज्यादा कमरे होना या 50 डेसिमल से ज्यादा जमीन होना, सिर्फ इसी वजह से उन्हें योजना से बाहर नहीं किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले महीने कई पात्र महिलाओं को पैसा न मिलने पर सवाल उठे थे। अब गांव में तीन से ज्यादा कमरे वाली महिलाओं को भी फायदा मिलेगा। इससे ग्रामीण महिलाओं की संख्या बढ़ेगी। जिन महिलाओं को दूसरी सरकारी योजनाओं से 3000 रुपये से कम मिल रहा है, उन्हें अन्नपूर्णा योजना से बाकी अंतर राशि दी जाएगी।

जेन जी और जेन अल्फा ने उड़ाई बिहार पुलिस की नींद, स्कूल की समस्याओं पर तुरंत कार्रवाई के आदेश

मुजफ्फरपुर (संवाददाता)। बिहार में जेन जी और जेन अल्फा के सवालों ने पुलिस और प्रशासन की नींद उड़ा दी है। खासकर, स्कूलों की छोटी-बड़ी समस्याओं को छात्र-छात्राएं सोशल मीडिया और सड़क तक आंदोलन का मुद्दा बनाए जाने लगा है। स्कूलों में मिलने वाले मिड डे मील (मध्याह्न भोजन) की गुणवत्ता को लेकर बच्चे अब मुखर रूप से सवाल उठाने लगे हैं। राज्य के अलग-अलग जिलों से ऐसे 40 मामले सामने आ चुके हैं। इसके बाद संबंधित जिलों के डीईओ को तुरंत कार्रवाई का आदेश दे दिया गया है। पुलिस महानिदेशक की ओर से इस संबंध में शिक्षा विभाग को भी पत्र भेजा गया है।

मुजफ्फरपुर समेत अन्य कुछ जिलों के डीईओ को ऐसे मामलों की पूरी सूची भेजी गई है। स्कूलों की इन घटनाओं को आंदोलन का मुद्दा बनाए जाने पर उन्होंने चिंता भी जताई है। साथ ही मिड डे मील से जुड़ी शिकायतों की जांच कर त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। इन मामलों में स्कूली बच्चों को मिलने वाले भोजन के खराब होने, खाने में कीड़ा मिलने, चावल आदि बेच देने की शिकायतें अधिक हैं।

हाल के दिनों में बिहार में कई जगहों पर मिड डे मील में गड़बड़ी के विरोध में स्कूली छात्र सड़क पर उतरकर हंगामा कर चुके हैं। गांव के अन्य युवक और अभिभावक भी उनका साथ दे चुके हैं। पुलिस महानिदेशक विशेष शाखा ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को इन में कार्रवाई को लेकर पत्र लिखा है। मध्याह्न भोजन निदेशक विनायक मिश्र ने सभी जिलों को निर्देश दिया है।

मामलों को सोशल मीडिया पर वायरल करने को लेकर भी चिंता जताई गई है। जेन जी और खासकर जेन अल्फा पीढ़ी गड़बड़ी को लेकर बहुत ही जागरुक हो रही है। मुजफ्फरपुर में ऐसी 6 से अधिक ऐसी घटनाएं हुई हैं। गयाजी में हाल ही में मिड डे मील में कीड़ा मिलने पर बच्चे पुलिस थाने पहुंच गए थे।

मुजफ्फरपुर में हो चुके हैं जेन अल्फा का प्रदर्शन : 28 जनवरी को जिले के कटरा प्रखंड के डुमरी मध्य विद्यालय में सही ढंग से मध्याह्न भोजन नहीं मिलने के कारण हंगामा हुआ था। आरोप है कि स्कूल में 200 बच्चे हैं, लेकिन सभी के लिए भोजन नहीं बनता है। इसके बाद 11 मई को कांटी, मुशहरी के स्कूलों में हंगामा हुआ। इन जगहों पर भोजन की थाली में कीड़ा मिलने के कारण जेन अल्फा ने हंगामा किया था। अभिभावकों को आक्रोश था कि खाना घटिया किस्म का होता है। नालंदा जिले में भी 20 मई को एमडीएम खाने से 39 बच्चों की तबीयत खराब हुई थी।

अन्य जिलों में भी हो चुके हैं प्रदर्शन

पत्र के अनुसार, जनवरी से अगस्त तक इस मुद्दे को लेकर आंदोलन करने के मामले में कार्रवाई का आदेश दिया गया है। मधेपुरा में 17 जनवरी को गहुमनी इटहरी मध्य विद्यालय में खाने के दौरान एक बच्चे के थाली में छिपकली देख बच्चा चिल्लाया। इसके बाद शोर शराबा और हंगामा के बीच मधेपुरा मेडिकल कॉलेज में 50 बच्चों को भर्ती कराया गया। इसी तरह कटिहार में 2 फरवरी में आदर्श म. वि. खैरा में चावल चोरी होने का वीडियो वायरल हुआ और बच्चों-अभिभावकों ने स्कूल में हंगामा किया। मधेपुरा में ही 7 फरवरी को मिड डे मिल खाने से 70 बच्चे बीमार हुए। सीतामढ़ी में 11 फरवरी को, कटिहार में 18 से 21 फरवरी के बीच मध्याह्न भाजन में कटौती और दाल की जगह आलू देने को लेकर बच्चों ने हंगामा किया। जमुई में 8 अप्रैल, मोतिहारी में 17 अप्रैल, सहरसा में 7 मई, 8 मई, अररिया में आठ मई को बच्चों ने विरोध प्रदर्शन किया।

लखनऊ होकर बंगाल, बिहार और पंजाब के लिए 2 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, यात्रियों को राहत

पटना (संवाददाता)। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के सीनियर डीसीएम समर्थ गुप्ता के अनुसार ट्रेन संख्या 04312/04311 योग नगरी ऋषिकेश-कोलकाता-योग नगरी ऋषिकेश आरक्षित त्योहार विशेष ट्रेन योग नगरी ऋषिकेश से 16 अक्तूबर से 20 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार और कोलकाता से 18 अक्तूबर से 22 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को चलेगी। 04312 योग नगरी ऋषिकेश से 22:20 बजे चलेगी। हरिद्वार, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर होते हुए लखनऊ मंडल के आलमनगर स्टेशन पर आगमन अगले दिन सुबह 09:10 बजे पहुंचेगी। यहां से 09:20 बजे चलकर उतरेठिया जंक्शन पर 09:48 बजे पहुंच कर 09:50 बजे चलेगी।

रायबरेली, मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ वाराणसी, पं. दीन दयाल उपाध्याय, भभुआ रोड, सासाराम, डेहरी ऑन सोन, अनुग्रह नारायण रोड, गया, कोडरमा, हजारीबाग रोड, पारसनाथ, एनएससी बोस गोमो, धनबाद, आसनसोल, दुर्गापुर, बर्द्धमान, बंडेल एवं नैहाटी होते हुए कोलकाता अगले दिन 8:00 बजे पहुंचेगी। वापसी में 04311 कोलकाता से 13:55 बजे चलेगी। उक्त स्टेशनों से होते हुए अगले दिन उतरेठिया 11:30 पहुंच कर 11:32 बजे चलेगी। आलमनगर स्टेशन पर दोपहर 12:00 बजे एवं प्रस्थान 12:10 बजे करेगी। इसके बाद शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद एवं हरिद्वार होते हुए योग नगरी ऋषिकेश पहुंचेगी।

अमृतसर से बरौनी के बीच 04 अक्तूबर से- ट्रेन संख्या 04668/04667 अमृतसर-बरौनी-अमृतसर आरक्षित विशेष ट्रेन अमृतसर से 04 अक्तूबर से 29 नवंबर तक प्रत्येक रविवार और बरौनी से 06 अक्तूबर से 01 दिसंबर तक प्रत्येक मंगलवार को चलेगी। ट्रेन 04668 अमृतसर से 20:10 बजे चलेगी। ब्यास, जालंधर सिटी, फगवाड़ा, धंडारी कलां, अंबाला कैंट, यमुनानगर-जगाधरी, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई होते हुए लखनऊ मंडल के आलमनगर स्टेशन पर अगले दिन 10:30 बजे पहुंच कर 10:40 बजे चलेगी। रायबरेली, मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़, वाराणसी, औंड़िहार, गाजीपुर सिटी, बलिया, छपरा, छपरा ग्रामीण, सोनपुर, हाजीपुर एवं शाहपुर पटोरी होते हुए बरौनी जंक्शन पहुंचेगी।

बेतिया में महिला की बेरहमी से हत्या

गला रेता, दो उंगलियां काटकर सिर के पास रख दी

बेतिया (संवाददाता)। बिहार के बेतिया शहर में बुधवार को एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। वारदात कालीबाग थाना क्षेत्र के हरिहरनगर वार्ड 5 स्थित नोनिया टोली में अहले सुबह हुई। मृतका की पहचान बच्ची देवी के रूप में हुई है। उनकी उम्र लगभग 55 साल थी। बताया जा रहा है कि बच्ची देवी जब अपने घर में सो रही थी, तभी धारदार हथियार से उनका गला रेत दिया गया। हत्यारों ने उनकी बाएं हाथ की दो उंगलियां भी काट दीं और उन्हें सिर के पास रख दिया।

इस जघन्य हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। महिला के पति का 3 साल पहले निधन हो चुका है। परिजन का कहना है कि उनका दो मंजिला मकान है। उसमें पांच कमरे हैं। परिवार के अन्य सदस्य अलग-अलग कमरों में सो रहे थे। तभी बच्ची देवी की हत्या की गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार तड़के करीब 4 बजे घर की बड़ी बहू अंजू देवी ने अपनी देवरानी पूजा देवी और सुमन कुमारी को जगाकर कि बच्ची देवी के साथ कुछ अनहोनी हो गई है। परिजन कमरे में पहुंचे तो बच्ची देवी बिस्तर पर मृत अवस्था में पड़ी हुई थीं। उनके चेहरे पर कपड़ा रखा हुआ था। कपड़ा हटाने पर गला रेता हुआ मिला। बाएं हाथ की दो उंगलियां कटी थीं, जिन्हें सिर के पास रखा गया था। दाएं हाथ पर भी धारदार हथियार से जख्म के निशान मिले। घटना की सूचना मिलते ही कालीबाग थाना पुलिस मौके पर पहुंची। एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए। पुलिस ने परिवार के सदस्यों से पूछताछ करने के साथ घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। परिजनों ने बताया कि करीब 3 महीने पहले ही घर में मोबाइल चोरी हुआ था। इसके बाद सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे।

भाई वीरेंद्र के ऑफर को नहीं मिला जेडीयू से भाव, अब निशांत को सीएम बनाने के सवाल पर भी बोले

पटना (संवाददाता)। लालू-तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र के ऑफर को नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेडसे भाव नहीं मिला है। दूसरी ओर, राजद नेता अपने ऑफर पर कायम हैं। उन्होंने बुधवार को एक बार फिर जदयू को भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़कर राजद के साथ सरकार बनाने का न्योता दे दिया। इस बार उन्होंने जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के बेटे एवं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत को मुख्यमंत्री बनाने के सवाल पर भी खुलकर बात की है।

राजद के सीनियर नेता और मनेर से विधायक भाई वीरेंद्र ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में कहा, 'हमारा बयान स्पष्ट है। नीतीश कुमार समाजवादी राजनीतिक पृष्ठभूमि के रहे हैं। उन्होंने ही बिहार में भाजपा के पैर जमाए। वे यह पाप नहीं करते तो भाजपा यहां नहीं पनपती। गंगाजल से पाप धोने का समय आ गया है। नीतीश ने बिहार में यूसीसी नहीं लागू करने का स्टैंड लिया हुआ है। इस मुद्दे पर भाजपा से अलग होइए और आइए महागठबंधन में, मिलजुलकर सरकार बनाएं और भाजपा को भगाएं।' उन्होंने यह स्पष्ट किया कि वह जदयू को एनडीए छोड़ महागठबंधन में आने का सिर्फ न्योता दे रहे हैं, नीतीश की पार्टी के नेताओं से वह संपर्क में नहीं हैं। भाई वीरेंद्र से जब पूछा गया कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है, तो क्या नीतीश के बेटे निशांत कुमार को राजद मुख्यमंत्री बनाने पर सहमत होगी? क्योंकि जदयू के पास 85 विधायक हैं, जबकि राजद के सिर्फ 25 एमएलए हैं। इसका जवाब देते हुए राजद विधायक ने कहा कि यह सवाल ही पैदा नहीं होता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब भी उनकी पार्टी के साथ सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही होंगे।

यूसीसी पर सियासत

राजद की ओर से जदयू को गठबंधन का न्योता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के यूसीसी लागू करने के ऐलान के बाद आया है। तेजस्वी की पार्टी इसके विरोध में हैं। वहीं, जदयू के स्टैंड पर फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है। पहले जदयू विधायक श्याम रजक ने कहा कि बिहार में यूसीसी लागू नहीं होने देंगे। उसके बाद डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने कहा कि यूसीसी का ड्राफ्ट आने के बाद इसके प्रावधानों को देखा जाएगा, फिर जदयू उस पर विचार करेगी।

राजद को नहीं मिला जदयू से भाव!

राजद विधायक की ओर से जदयू को गठबंधन का ऑफर मिलने के बाद बिहार का सियासी पारा गर्माया हुआ है। हालांकि, भाई वीरेंद्र को अभी तक जदयू से कोई भाव नहीं मिला है। उन्होंने एक दिन पहले भी जदयू को गठबंधन बदलने का न्योता दिया था। बिहार के डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने मंगलवार को ही स्पष्ट कर दिया था कि राजद क्या चाहती है, इससे जदयू को कोई मतलब नहीं है।

छठ-दिवाली स्पेशल ट्रेनों में अमृत भारत के रैक दौड़ेंगे, किराये में यात्रियों को बड़ी राहत

मुजफ्फरपुर (संवाददाता)। दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ समेत अन्य त्योहारों पर रेलवे बिहार-यूपी रूट पर बड़ी संख्या में स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रहा है। इस बार कई स्पेशल ट्रेनों को आधुनिक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के रैक से चलाया जाएगा। आम तौर पर अमृत भारत ट्रेनों का किराया अन्य मेल एवं एक्सप्रेस ट्रेनों से अधिक होता है। हालांकि, फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों में यात्रियों से अधिक किराया नहीं वसूला जाएगा। रेलवे बोर्ड ने अमृत भारत रैक से चलने वाली स्पेशल ट्रेनों के किराये को लेकर एक सर्कुलर भी जारी किया है।

रेलवे बोर्ड ने ऐसी ट्रेनों को मेल एवं एक्सप्रेस स्पेशल की श्रेणी में रखने का फैसला लिया है। इनका किराया 21 मई 2015 को जारी हुए आदेश के अनुसार ही लिया जाएगा, जो अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों से कम होगा। ऐसे में स्पेशल ट्रेनों से सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। रेलवे बोर्ड के निदेशक पैसेंजर मार्केटिंग एंड कॉओर्डिनेशन प्रवीण कुमार ने इस संबंध में पत्र जारी किया है। उसमें कहा गया है कि यह किराया व्यवस्था अगले 6 महीने तक लागू रहेगी। यानी कि दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ और होली तक चलने वालीं स्पेशल ट्रेनों के यात्रियों को राहत मिलती रहेगी। रेलवे की बुकिंग साइट के अनुसार, अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का बेस किराया सामान्य मेल अथवा एक्सप्रेस ट्रेनों से 15 से 17 प्रतिशत ज्यादा होता है। जैसे सामान्य ट्रेन में 1 से 50 किलोमीटर का जनरल कोच का मिनिमम किराया 30 रुपये है तो अमृत भारत में यह 35 रुपये होता है।

रेलवे बोर्ड ने नए आदेश में वर्ष 2015 में किए गए बदलाव को आधार बनाया है। 2015 में स्लीपर में 175 रुपये, एसी चेयर कार में 200 रुपये, थर्ड एसी में 350 रुपये तथा सेकेंड एसी, एक्जीक्यूटिव चेयर कार और फर्स्ट एसी में 400 रुपये तक स्पेशल चार्ज का प्रावधान किया गया था। अमृत भारत रैक वाली कोई ट्रेन स्पेशल सेवा के रूप में चलाई जाती है तो यात्रियों के लिए ट्रेन की श्रेणी मेल-एक्सप्रेस की ही होगी। बोर्ड ने यह स्पष्ट किया है कि रैक अमृत भारत का होने से नियमित अमृत भारत एक्सप्रेस का किराया लागू नहीं होगा।

दारोगा बहाली में धांधली से जुड़े बीपीएससी के जवाब से ईओयू असंतुष्ट

टॉप परीक्षा केंद्रों की लिस्ट भी नहीं मिली

पटना (संवाददाता)। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने दारोगा भर्ती परीक्षा में हुई कथित धांधली से जुड़े प्रश्नों के जवाब आर्थिक अपराध इकाई को सौंप दी है। मंगलवार को भी दो पत्र बीपीएसएससी को भेज जवाब मांगा। रिपोर्ट में पूर्णिया और गया जी में परीक्षा के दौरान हुई धांधली में आयोग के स्तर से की गई कार्रवाई के साथ परीक्षा केंद्रों का सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराया गया है। हालांकि, ईओयू सूत्रों के मुताबिक, आयोग की रिपोर्ट में कई प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट नहीं हैं। ईओयू द्वारा गठित एसआईटी दारोगा भर्ती परीक्षा में धांधली से संबंधित आरोपों की जांच कर रही है। एसआईटी ने तीन सितंबर को बीपीएसएससी को पत्र लिख दोनों जिलों के केंद्रों में हुई गड़बड़ियों से संबंधित कई जानकारियां मांगी थीं।

इसके बाद ईओयू ने 8 सितंबर को भी आयोग से जानकारी मांगी। ईओयू ने कुछ परीक्षा केंद्रों पर 25 से 30 प्रतिशत तक अभ्यर्थियों के उत्तीर्ण होने की शिकायत मिलने पर सबसे अच्छे रिजल्ट वाले टॉप-20 परीक्षा केंद्रों की सूची भी मांगी थी। इसका उत्तर अभी नहीं मिला है। आयोग के स्तर से दिए गए प्रश्नों के उत्तर संतोषप्रद है या नहीं, इसको लेकर एसआइटी अभी जवाब का अध्ययन कर रही है। इसमें बिंदुवार प्रश्नों के जवाब और कार्रवाई के बारे में मिली जानकारी का सत्यापन किया जा रहा है। इसके बाद ईओयू अगला कदम उठायेगा।

बता दें कि दारोगा परीक्षा बहाली में कथित गड़बड़ियों की जांच के क्रम में आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) की एसआईटी ने बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग से कई बिंदुओं पर जवाब मांगा था। ईओयू ने परीक्षार्थियों के अनुपात में सर्वाधिक रिजल्ट देने वाले टॉप 20 परीक्षा केंद्रों की सूची भी तलब की थी। साथ ही ऐसे शीर्ष 20 परीक्षा केंद्रों से संबंधित ब्योरा भी मांगा था जहां के क्रमवार रोल नम्बर के अधिक विद्यार्थी सफल हुए हैं। ईओयू ने बीपीएसएससी को तीन और आठ सितंबर को दो पत्र लिखे थे। जिसपर आयोग को जवाब देना था। ईओयू एसआईटी ने आयोग से शिकायत वाले परीक्षा केंद्रों के वीडियो फुटेज भी मांगे थे। इनमें पूर्णिया के साइबर थाना और गया जी के रामपुर थाना में दर्ज एफआईआर से संबंधित परीक्षा केंद्र के साथ ही छात्रों की आपत्ति वाले परीक्षा केंद्र भी शामिल हैं। इन केंद्रों के तत्कालीन केंद्राधीक्षक से लेकर वीक्षक, बायोमेट्रिक व जैमर कर्मियों की सूची मांगी गयी है।

पेपर लीक के प्रमाण नहीं

ईओयू सूत्रों के मुताबिक, अब तक की जांच में परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र लीक से संबंधित कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। हालांकि, पूर्णिया में एक शिक्षक द्वारा वाट्सअप से पटना भेजी गयी प्रश्न पत्र की कॉपी और गया जी में परीक्षा के दौरान मिले डिजिटल प्रमाणों के आधार पर परीक्षा माफिया के संबंधों की तलाश की जा रही है।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जंगल में फंसी सांसद पप्पू यादव की नाव, सुरक्षित निकले

समस्तीपुर (संवाददाता)। बिहार के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव उस वक्त मुसीबत में फंस गए जब वो इन्हीं बाढ़ प्रभावितों का सूरत-ए-हाल देखने निकले थे। दरअसल समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीननगर प्रखंड में मंगलवार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का जायजा लेने पहुंचे पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की नाव बदिया गांव जाने के दौरान घने जंगल और जलकुंभी में फंस गई।

बताया जा रहा है कि नाव कुरसाहा पंचायत के बदिया गांव स्थित दलित-महादलित टोले की ओर जा रही थी। काफी मशक्कत के बाद नाव को बाहर निकाला गया। घटना में सांसद समेत नाव पर सवार किसी व्यक्ति के हताहत होने की सूचना नहीं है। सांसद पप्पू यादव बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए मोहिउद्दीननगर पहुंचे थे। इसी क्रम में पप्पू यादव नाव से कुरसाहा पंचायत के बदिया गांव के दलित-महादलित टोले की ओर जा रहे थे। बाढ़ के पानी के बीच घने जंगल और जलकुंभी के कारण नाव आगे नहीं बढ़ सकी और वहीं फंस गई। इससे नाव पर सवार लोगों के बीच कुछ देर अफरातफरी की स्थिति रही। स्थानीय लोगों, सुरक्षाकर्मियों और सांसद के साथ मौजूद सहयोगियों ने नाव को निकालने का प्रयास शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद नाव को झाड़ियों और जलकुंभी से बाहर निकाला गया। इसके बाद सांसद बदिया गांव पहुंचे और बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनकी स्थिति की जानकारी ली।

पप्पू यादव दलित-महादलित सहित कई विभिन्न टोले के बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनके स्थिति से अवगत हुए। बदिया के दलित-महादलित टोले में घर-घर जाकर भोजन, आवागमन, पशुचारा, आर्थिक संकट और राहत व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं से अवगत हुए। इस दौरान जरूरतमंद परिवारों के बीच उन्होंने अपने निजी कोष से 3.50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई। भ्रमण के दौरान वे हसनपुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित महिलाओं और लड़कियों से संवाद किया। बदिया गांव मे बाढ़ के पानी में डूबने से जान गंवाने वाले के परिजनों से मिलकर 10 हजार रुपये का आर्थिक सहयता की। दौरे के बाद पप्पू यादव ने राहत और और बचाव व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, चिराग पासवान और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के क्षेत्र की जनता बाढ़ की चपेट मे है। मंत्री के क्षेत्र की स्थिति और खराब है। सांसद की नाव फंसने की घटना के बाद बाढ़ प्रभावित दियारा क्षेत्र में आवागमन की स्थिति को लेकर सवाल उठे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बाढ़ के कारण कई इलाकों में सामान्य आवागमन प्रभावित है।

श्राद्धकर्म का भोज खाकर 50 लोग बीमार, 6 लोगों की हालत चिंताजनक

पटना (संवाददाता)। पटना से सटे बिहटा में एक भोज खाने के बाद करीब 50 लोग बीमार पड़ गए। दरअसल पटना से सटे बिहटा प्रखंड के कंचनपुर गांव में 50 लोग अचानक बीमार हो गए। सभी ने रात गांव में हुए एक श्राद्धकर्म का भोज खाया था। उल्टी-दस्त होने के बाद प्रभावितों को रेफरल अस्पताल और निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें आधा दर्जन लोगों की हालत चिंताजनक बताई जा रही है।

वहीं गंभीर हालत में 10 वर्षीय पिंकी कुमारी को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। घटना के बाद प्रशासन प्रभावितों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के साथ ही बीमार होने के कारणों की जांच में जुट गया है। कंचनपुर गांव में सुनील सिंह की बरखी पर सोमवार को श्राद्ध का भोज रखा गया था। भोज में गांव के लोगों ने सोमवार रात चावल-दाल का भोजन किया था। मंगलवार तड़के भोज खाने वाले कई लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। किसी के पेट में तेज दर्द तो किसी को उल्टी-दस्त होने लगा। इससे गांव में अफरातफरी मच गई । लोगों ने आनन-फानन में सभी को इलाज के लिए सरकारी और निजी अस्पतालों में भर्ती कराया। करीब 21 लोगों को रेफरल अस्पताल और 29 लोगों को निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। प्रभावित लोगों की पहचान कंचनपुर निवासी शत्रुंजय कुमार, दीपक कुमार, कृष्णा कुमार, आदित्य, निधि कुमारी, मोहित के रूप में हुई है।

बिहार पंचायत चुनाव में अत्यंत पिछड़ा वर्ग आरक्षण का नया मानक जल्द, 50 फीसदी की सीमा में तय होगा कोटा

पंचायतवार आबादी, सामाजिक-शैक्षणिक स्थिति और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होगा आकलन; अनुसूचित जाति-जनजाति के आरक्षण के बाद बची सीमा में ही मिलेगा अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटा

पटना (संवाददाता)। बिहार में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का मानक जल्द तय होने की संभावना है। पंचायती राज विभाग की विशेषज्ञ टीम ने आरक्षण के मानक से संबंधित दिशा-निर्देश का मसौदा तैयार किया है। यह दिशा-निर्देश एक महीने के भीतर अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयोग को भेजे जाने की तैयारी है। इसी दिशा-निर्देश के आधार पर आयोग पंचायत चुनाव में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के प्रतिशत को लेकर अपनी अनुशंसा करेगा।

पंचायत चुनाव में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को लेकर सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कुल आरक्षण किसी भी स्थिति में 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसे में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का वास्तविक प्रतिशत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी तथा उनके लिए निर्धारित आरक्षण के बाद उपलब्ध सीमा के आधार पर तय किया जाएगा। प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार जनगणना के आधार पर राज्य की कुल आबादी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जितनी आबादी होगी, उन्हें उसी अनुपात में आरक्षण दिया जाना है। इसके बाद 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के भीतर बची हुई हिस्सेदारी में ही अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण तय किया जा सकेगा। मसलन, यदि किसी स्थिति में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी कुल आबादी की 40 प्रतिशत है, तो उन्हें 40 प्रतिशत आरक्षण देने के बाद 50 प्रतिशत की सीमा में केवल 10 प्रतिशत हिस्सा ही अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए उपलब्ध रहेगा। इसी वजह से आगामी पंचायत चुनाव में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का प्रतिशत पहले से निर्धारित करने के बजाय तय मानकों और पंचायतवार स्थिति के अध्ययन के आधार पर तय किया जाएगा। बीते पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग को 20 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को 30 प्रतिशत आरक्षण मिला था। आगामी चुनाव के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग आरक्षण का नया निर्धारण संबंधित अध्ययन और लागू नियमों के आधार पर किया जाना है। पंचायत चुनाव में अत्यंत पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने से पहले तीन स्तरों पर जांच और अध्ययन की व्यवस्था महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसमें सबसे पहले यह सुनिश्चित किया जाना है कि कुल आरक्षण 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक न हो। इसके बाद यह देखा जाएगा कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग की किन जातियों और समुदायों को वास्तव में आरक्षण की आवश्यकता है। इसके लिए एक समर्पित आयोग द्वारा अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार की जानी है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयोग को इसी अध्ययन के आधार पर पंचायतों में अत्यंत पिछड़ा वर्ग की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का आकलन करना होगा। आयोग की रिपोर्ट के बाद सरकार आगे की प्रक्रिया पूरी करेगी। नई व्यवस्था में आरक्षण का निर्धारण केवल राज्य स्तर पर एक समान प्रतिशत तय करके नहीं किया जाएगा। इसके बजाय पंचायत को अध्ययन और आकलन की इकाई बनाया जाएगा।

प्रत्येक पंचायत में अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी, उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति तथा विभिन्न निर्वाचित संस्थाओं में उनके प्रतिनिधित्व की स्थिति का अध्ययन किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि पंचायत स्तर पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग समुदायों की वास्तविक जनसंख्या कितनी है और विभिन्न क्षेत्रों में उनका प्रतिनिधित्व किस स्थिति में है। आयोग को इसी आधार पर आरक्षण से संबंधित अपनी अनुशंसा तैयार करनी होगी। पंचायती राज विभाग की प्रस्तावित दिशा-निर्देश में केवल आबादी को ही आधार नहीं बनाया गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के परिवारों की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और शैक्षणिक स्थिति का भी अध्ययन किया जाएगा। इसके साथ ही विभिन्न निर्वाचित संस्थाओं में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व की जानकारी भी जुटाई जाएगी। दिशा-निर्देश में संसद, विधानसभा, नगर निकाय और पंचायतों में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के वर्तमान प्रतिनिधित्व को भी अध्ययन का हिस्सा बनाया गया है। इस तरह आयोग को यह आकलन करना होगा कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग को अलग-अलग स्तरों पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व किस अनुपात में मिला है। बिहार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग की सूची में लगभग 122 जातियां शामिल हैं। आयोग को यह भी देखना होगा कि पंचायत चुनावों में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का लाभ सभी संबंधित जातियों तक पहुंच रहा है या नहीं। विशेष रूप से यह अध्ययन किया जाएगा कि कहीं पंचायतों में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए उपलब्ध राजनीतिक प्रतिनिधित्व केवल कुछ जातियों तक ही सीमित तो नहीं रह जा रहा है। प्रमुख अत्यंत पिछड़ा वर्ग जातियों में कहार, कुम्हार, धानुक, लोहार, तेली, मल्लाह, कानू और नाई आदि शामिल हैं। आयोग इन समुदायों की पंचायतवार स्थिति का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा। बिहार की पंचायतों में कुल जनप्रतिनिधियों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान भी लागू है। ऐसे में पंचायत चुनाव में विभिन्न आरक्षित वर्गों के लिए सीटों का निर्धारण करते समय महिलाओं के आरक्षण से जुड़े प्रावधानों को भी ध्यान में रखा जाएगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग आरक्षण की नई प्रक्रिया में पंचायतवार आबादी और प्रतिनिधित्व के साथ सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का अध्ययन किए जाने के कारण आने वाले पंचायत चुनावों में आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया पिछले चुनावों की तुलना में अधिक विस्तृत हो सकती है।

पंचायती राज विभाग की विशेषज्ञ टीम द्वारा तैयार किए गए मानकों को अब अंतिम रूप देकर अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयोग को भेजने की तैयारी है। विभाग के स्तर से यह दिशा-निर्देश लगभग एक महीने के भीतर आयोग को भेजी जा सकती है। इसके बाद आयोग निर्धारित मानकों के आधार पर पंचायतों में अत्यंत पिछड़ा वर्ग की स्थिति का अध्ययन करेगा। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा है कि पंचायत चुनाव में अत्यंत पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए सरकार ने अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयोग को समर्पित आयोग घोषित किया है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज विभाग की ओर से जल्द ही आयोग को अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अध्ययन से संबंधित दिशा-निर्देश भेज दी जाएगी। दिशा-निर्देश मिलने के बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयोग पंचायतों में अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी, आर्थिक स्थिति, सामाजिक एवं शैक्षणिक स्थिति और राजनीतिक प्रतिनिधित्व सहित निर्धारित मानकों का अध्ययन करेगा। आयोग की रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। इसके बाद सरकार रिपोर्ट को निर्वाचन विभाग को भेजेगी, जिसके आधार पर पंचायत चुनाव में आरक्षण से जुड़ी आगे की प्रक्रिया पूरी होगी।

इस पूरी व्यवस्था में यह महत्वपूर्ण है कि आरक्षण का अंतिम निर्धारण राज्य स्तर पर एक समान प्रतिशत के आधार पर नहीं होगा, बल्कि पंचायत को मानक बनाया जाएगा। यानी अलग-अलग पंचायतों में अत्यंत पिछड़ा वर्ग की स्थिति के अध्ययन के आधार पर आरक्षण का निर्धारण किया जा सकेगा। प्रस्तावित दिशा-निर्देश में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के आरक्षण निर्धारण के लिए कुल आरक्षण का दायरा किसी भी स्थिति में 50 प्रतिशत से अधिक नहीं रखने, प्रत्येक पंचायत में अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी का आकलन करने, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के परिवारों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने, संसद, विधानसभा, नगर निकाय और पंचायतों में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के वर्तमान प्रतिनिधित्व को देखने तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग की सामाजिक एवं शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करने जैसे मानकों को शामिल किया गया है। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग आरक्षण का प्रतिनिधित्व कुछ चुनिंदा जातियों तक ही सीमित तो नहीं है।

बिहार के आगामी पंचायत चुनाव में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का निर्धारण 50 प्रतिशत की अधिकतम आरक्षण सीमा के भीतर किया जाएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी तथा उनके आरक्षण के बाद उपलब्ध हिस्से के आधार पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की गुंजाइश तय होगी। इसके लिए पंचायतवार आबादी, आर्थिक स्थिति, सामाजिक-शैक्षणिक स्थिति और विभिन्न निर्वाचित संस्थाओं में प्रतिनिधित्व का अध्ययन किया जाएगा।

टेंपो में बैठी महिला को ड्राइवर से हो गया इश्क, होटल में पकड़े गए दोनों; लोगों ने करा दी शादी

जहानाबाद (संवाददाता)।

बिहार के जहानाबाद जिले से प्रेम प्रसंग का एक रोचक मामला सामने आया है। एक शादीशुदा महिला को टेंपो चलाने वाले एक युवक से प्यार हो गया। महिला उसके टेंपों में सवार हुई थी, उसी दौरान आंखें-चार हो गईं। युवक खुद भी शादीशुदा और चार बच्चों का पिता है। एक साल तक दोनों के बीच चोरी-छिपे अफेयर चलता रहा। हाल ही में जब वे एक होटल में गए तो लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। फिर उनकी वहीं पर शादी भी करवा दी गई।

महिला जहानाबाद जिले के कड़ौना थाना क्षेत्र की रहने वाली है। वहीं, उसका प्रेमी पटना जिला के मसौढ़ी अनुमंडल स्थित भगवानगंज थाना क्षेत्र का निवसी है। मंगलवार की देर शाम तक प्रेमी जोड़े को कड़ौना थाना में लाया गया। उनके कुछ सगे-संबंधी भी मौजूद रहे। कड़ौना

के थानाध्यक्ष जगन्नाथ पासवान ने बताया कि इस मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लोगों ने दोनों की शादी रचा दी है।

फिलहाल पूछने पर कपल ने एक-दूसरे के साथ रहने की बात कही है। जानकारी के अनुसार कड़ौना थाना क्षेत्र अंतर्गत चिडैयाटांड (सेवनन) गांव के निवासी विजेंद्र कुमार की पत्नी काजल कुमारी और पटना जिले के रौनिया बारा (भगवानगंज) गांव निवासी रणधीर चौधरी के बीच करीब एक साल से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। युवक टेंपो चालक है जिसे पहले से चार बच्चे हैं। महिला एक बच्चे की मां है।

काजल करीब एक साल पहले रणधीर के टेंपों में सवार हुई थी। दोनों के मन में उसी समय इश्क की चिंगारी भड़क गई। उन्होंने एक-दूसरे का मोबाइल नंबर ले लिया। धीरे-धीरे प्रेम परवान चढ़ गया। मंगलवार को उस समय यह मामला पूरी तरह उजागर होकर चर्चा का विषय बन गया, जब दोनों को मसौढ़ी के एक होटल से पकड़ लिया गया। होटल से पकड़े जाने के बाद युवती के परिजन और ग्रामीण दोनों को चिरैयाटांड गांव ले आए और ग्रामीणों की मौजूदगी में उनकी शादी करा दी गई।

ससुराल वालों को हुआ शक, तो रंगे हाथों पकड़ी गई महिला

बताया गया है कि काजल का पति बाहर रहकर काम करता है। इसी दौरान उसके ससुराल वालों को दोनों के बीच संबंध होने का शक हुआ। काजल जब घर से निकली तो उसके पति और परिजन ने उसका पीछा किया। फिर वे मसौढ़ी स्थित उस होटल में पहुंचे गए, जहां रणधीर और काजल एक कमरे में थे।

पति की प्रेमिका से शादी होते देख रोने लगी पत्नी

होटल में पकड़े जाने के बाद दोनों को गांव लाकर शादी करा दी गई। इस दौरान टेंपो ड्राइवर की पहली पत्नी भी अपने चारों बच्चों के साथ मौके पर मौजूद थी। अपने पति को उसकी प्रेमिका के साथ शादी के बंधन में बंधते देख उसकी रुलाई फूट पड़ी। यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।

आशीर्वाद का दीया कार्यक्रम पर बोले तेजस्वी

मोदी के बर्थडे पर बाढ़ पीड़ितों का जिया जलाएगी बीजेपी

पटना (संवाददाता)।

बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आयोजित होने वाले 'आशीर्वाद का दीया' कार्यक्रम पर तीखा तंज कसा है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी के बर्थडे पर बिहार में 100 करोड़ रुपये के दीया-बाती और तेल के साथ-साथ बाढ़ पीड़ितों का जिया भी जलाएगी। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी ने यह भी कहा कि बिहार में बाढ़ पीड़ितों को देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, लेकिन ये लोग मोदी के लिए 100 करोड़ रुपये फूंकने को तैयार है।

तेजस्वी यादव ने बुधवार को पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि बिहार की जनता बाढ़, बेरोजगारी और महंगाई से मर रही है। मगर एनडीए सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 100 करोड़ रुपये का दीया-बाती जलाने जा रहे हैं, यह बहुत अजीब बात है। उन्होंने पीएम पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी कौन-से अच्छे दिन ले आए। देश के लोग परेशान हैं। ना पढ़ाई हो रही है, ना दवाई मिल रही है। बाढ़ से लोग मर रहे हैं, तो ये अपना दीया-बाती जलवा रहे हैं।

तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में बाढ़ से त्राहिमाम मचा हुआ है। लगभग 49 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। उनकी सहायता के बजाय डबल इंजन की एनडीए सरकार, पीएम मोदी के प्रचार में 100 करोड़ रुपये बहाने जा रही है।

पीएम के जन्मदिन पर विशेष अभियान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को जन्मदिन है। इस अवसर पर बीजेपी की ओर से देश भर में सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत, विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। गुरुवार को पीएम के जन्मदिन के अवसर पर आशीर्वाद का दीया कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। यह कार्यक्रम 7 अक्टूबर तक चलेगा। इसके जरिए बिहार के ढाई करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए बीजेपी के मंत्रियों से लेकर पार्टी पदाधिकारियों को टास्क दिया जा चुका है।

घर-घर दीये पहुंचाए जाएंगे

बिहार भाजपा की ओर से इस अभियान को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। लोगों को जन वितरण दुकानों, आंगनबाड़ी केंद्रों और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से दीयों का वितरण किया जाएगा। वहीं, हर जिले में प्रमुख स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर सामूहिक दीप प्रज्जवलन किया जाएगा।

डीजीपी का प्रभार संभालने वाली आईपीएस प्रीता वर्मा कौन हैं, यह अहम पुरस्कार भी मिल चुका है

पटना (संवाददाता)।

बिहार के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी विनय कुमार के 21 दिनों की छुट्टी पर जाने के बाद सम्राट चौधरी सरकार ने तेज-तर्रार आईपीएस अधिकारी प्रीता वर्मा को राज्य की प्रभारी डीजीपी बनाकर पुलिस विभाग की कमान सौंपी है। विनय कुमार की गैरहाजिरी में प्रीता वर्मा को कार्यकारी डीजीपी बनाया गया है। प्रीता वर्मा 1991 बैच की बिहार कैडर की आईपीएस अधिकारी हैं। पुलिस सेवा में प्रीता वर्मा को 3 दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। प्रीता वर्मा बिहार पुलिस की वरिष्ठ अधिकारियों में शामिल हैं। इसी साल जुलाई के महीने में उन्हें डीजी, होमगार्ड एवं अग्निशमन सेवा की जिम्मेदारी दी गई थी।

बताया जाता है कि प्रीता वर्मा का होम स्टेट राजस्थान है। बिहार पुलिस के शीर्ष पद की जिम्मेदारी संभालने वाली प्रीता वर्मा कई अहम पदों पर अपनी जिम्मेदारियां संभाल चुकी हैं और अपने सेवाकाल में उन्हें अहम पुरस्कार भी मिल चुका है। साल 2023 में बिहार के दो वरिष्ठ पुलिस अफसरों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया गया था। इसमें प्रीता वर्मा का भी नाम था। इससे पहले साल 2009 में प्रीता वर्मा को पुलिस मेडल भी मिल चुका है।

बिहार के मौजूदा डीजीपी विनय कुमार का कार्यकाल इसी साल के अंत में खत्म हो रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बिहार के नए स्थायी डीजीपी के तौर पर भी प्रीता वर्मा का नाम आगे चल रहा है। हालांकि, स्थायी डीजीपी की नियुक्ति की प्रक्रिया अलग है। इस प्रक्रिया के तहत राज्य गृह मंत्रालय 20 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नाम का पैनल तैयार कर उसे यूपीएससी को भेजेगा। यूपीएससी इसमें से तीन नामों को चुनेगी और फिर इसे राज्य सरकार को भेजा जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इसमें से बिहार के नए डीजीपी का चयन करेंगे।

राष्ट्रपति पुलिस पदक फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस पद से सम्मानित हो चुकी प्रीता वर्मा का नाम साल 2023 के MHA आईपीएस सिविल लिस्ट में DG(ट्रेनिंग)बिहार के पद पर दर्ज किया गया था।

बिहार में बाढ़ ने रोके टीचर ट्रांसफर

शिक्षा विभाग ने सामान्य तबादलों के आवेदन की तारीख आगे बढ़ाई

पटना (संवाददाता)।

बिहार में बाढ़ का असर सरकारी शिक्षकों के ट्रांसफर पर भी पड़ गया है। शिक्षा विभाग ने सामान्य तबादलों के लिए आवेदन की तारीख आगे बढ़ा दी है। सरकारी स्कूलों में खाली पदों की संशोधित वैकेंसी बुधवार को जारी होनी थी। मगर अब रिक्तियों का प्रकाशन अगले महीने किया जाएगा। उसी के बाद सामान्य ट्रांसफर के लिए शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। विभाग की ओर से नई तारीखों का ऐलान भी किया गया है।

शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से बुधवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई। इसमें बताया गया कि टीचर ट्रांसफर के पहले और दूसरे चरण की प्रक्रिया में हुई देरी को देखते हुए तीसरे चरण की निर्धारित समय-सारणी में बदलाव किया गया है। पहले और दूसरे फेज के ट्रांसफर की देरी के पीछे बाढ़ और आपदा को प्रमुख वजह बताया गया है।

टीचर ट्रांसफर की नई तारीखों का ऐलान : सरकारी स्कूलों में सरप्लस शिक्षकों के समायोजन और म्युचुअल ट्रांसफर के बाद सामान्य तबादलों के लिए संशोधित रिक्तियों का प्रकाशन 1 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा। इसमें हर स्कूल में शिक्षकों के खाली पदों की जानकारी दी जाएगी।

अधिसूचना में कहा गया कि पहले विद्यालयवार संशोधित रिक्तियों के प्रकाशन की तारीख 16 सितंबर तय थी। सामान्य ट्रांसफर के लिए शिक्षकों के ऑनलाइन आवेदन की अवधि 17 से 23 सितंबर निर्धारित की गई थी। हालांकि, संशोधित कार्यक्रम के तहत अब इन तिथियों को आगे बढ़ाकर अक्टूबर महीने में खिसका दिया गया है।

अब 4 अक्टूबर को खुलेगा ट्रांसफर पोर्टल

शिक्षकों के सामान्य ट्रांसफर के आवेदन की प्रक्रिया अब 4 अक्टूबर को शुरू होगी। टीचर 10 अक्टूबर तक अपनी इच्छानुसार विकल्प भरकर स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे। उन्हें वरीयता के आधार पर स्कूलों का चयन करना होगा।

नवंबर तक चलेगी ट्रांसफर की प्रक्रिया

ऐच्छिक तबादलों के लिए शिक्षकों से आवेदन मिलने के बाद शिक्षा विभाग इन पर विचार करेगा। इसके बाद जिला, प्रमंडल, राज्य स्थापना समिति के द्वारा सामान्य ट्रांसफर लिस्ट जारी कर दी जाएगी। फिर इस पर अपील का मौका दिया जाएगा, फिर उसका निपटारा होगा। इस पूरी प्रक्रिया में एक महीने से ज्यादा वक्त लगेगा।

एलजेपीआर नेता अंटू ईस्सर को कमरे का ताला तोड़ कर उठा ले गई पुलिस

मर्डर केस में जारी हुआ था वारंट

समस्तीपुर (संवाददाता)।

लोजपा (रामविलास) नेता सह सिने कारोबारी अंटू ईस्सर को एसटीएफ, डीआईयू और नगर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जहानाबाद के हुलासगंज निवासी भानु कुमार की हत्या मामले में हाजीपुर कोर्ट से उनकी गिरफ्तारी का वारंट निर्गत था। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस कई दिनों से कार्रवाई कर रही थी। मंगलवार को गुप्त सूचना के आधार पर बहादुरपुर स्थित उनके आवास पर छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार किया गया।

पुलिस टीम ने मकान को चारों तरफ से घेर लिया था। इस दौरान अंटू ईस्सर ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। दरवाजा नहीं खोलने पर मजिस्ट्रेट के रूप में मौजूद समस्तीपुर सीओ आदित्य शंकर की उपस्थिति में पुलिस ने कमरे का ताला तोड़ा और उन्हें बाहर निकाला। रात करीब 8:40 बजे उन्हें नगर थाने ले जाया गया। कार्रवाई के दौरान हथियार बरामदगी को लेकर भी जांच जारी थी।

नगर थानाध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया कि हाजीपुर कोर्ट से हत्याकांड में अंटू ईस्सर की गिरफ्तारी को लेकर वारंट निर्गत था। अंटू ईस्सर लोजपा (रामविलास) के संसदीय बोर्ड के प्रदेश सचिव हैं। उनकी गिरफ्तारी को लेकर पार्टी के जिलाध्यक्ष अनुपम कुमार सिंह उर्फ हीरा सिंह ने फिलहाल कुछ भी बोलने से परहेज किया है।

गांधी सेतु के पास मिला था जहानाबाद के भानु का शव

बता दें कि हाजीपुर गंगाब्रिज थाना क्षेत्र में 19 फरवरी को गांधी सेतु के पिलर संख्या एक के पास खड़ी ऑल्टो कार से जहानाबाद जिले के हुलासगंज निवासी मुरारी शर्मा के पुत्र भानु कुमार का शव बरामद हुआ था। पुलिस अनुसंधान में भानु कुमार के लोजपा (रामविलास) नेता सह सिने कारोबारी अंटू ईस्सर के समस्तीपुर स्थित बहादुरपुर में घर हुई फायरिंग में शामिल होने की बात सामने आने का दावा किया गया था। जांच में यह भी कहा गया था कि भानु की मौत अंटू की गोली से हुई थी। इसी मामले में अंटू ईस्सर के खिलाफ हाजीपुर कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी होने की बात पुलिस ने बताई है। 17 मार्च को कार व बाइक पर सवार लोगों ने अंटू के घर के बाहर फायरिंग की थी। इस घटना में उनके साथी शुभम सिंह उर्फ ईशू घायल हुए थे। पुलिस फायरिंग, भानु की मौत और हाजीपुर के हत्याकांड मामले के बीच संबंधों की जांच कर रही है।

राजमाता विजयराज कुमारी मेवाड़ का निधन, उदयपुर और पूरे मेवाड़ क्षेत्र में शोक की लहर

उदयपुर (एजेंसी)। मेवाड़ के पूर्व राजपरिवार की सदस्य राजमाता विजयराज कुमारी मेवाड़ के निधन के बाद राजस्थान के उदयपुर और पूरे मेवाड़ क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। लंबी बीमारी के बाद 83 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु पर उदयपुर, मेवाड़ और मारवाड़ में शोक की लहर दौड़ गई है। भारत और विदेश के प्रशंसक, सामाजिक संगठन और राजनीतिक नेता उनके जीवन और विरासत को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। अपनी गर्मजोशी, गरिमा और जन कल्याण के प्रति समर्पण के लिए याद की जाने वाली राजमाता विजयराज कुमारी ने शिक्षा और सामाजिक सेवा, विशेष रूप से उदयपुर में, महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके निधन से एक ऐसे व्यक्तित्व का युग समाप्त हो गया जो शहर की सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान से घनिष्ठ रूप से जुड़ा रहा।

राजमाता विजयराज कुमारी भारत के सबसे प्रतिष्ठित राजपरिवारों में से एक थीं। उनका जन्म गुजरात के कच्छ के पूर्व राजपरिवार में हुआ था और वे कच्छ के महाराज फतेह सिंह की छोटी पुत्री और कच्छ के महाराव की पोती थीं। विवाह के बाद, वे मेवाड़ के पूर्व राजपरिवार की सदस्य बनीं और स्वर्गीय अरविंद सिंह मेवाड़ की पत्नी बनीं। वे डॉ. लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ की माता भी थीं, जो एक प्रख्यात समाजसेवी और शिक्षाविद हैं और मेवाड़ परिवार की वर्तमान पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं।

राजमाता विजयराज कुमारी ने अपने पूरे जीवन में पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ-साथ मेवाड़ की परंपराओं और लोक सेवा के चिरस्थायी मूल्यों को संरक्षित करने की गहरी प्रतिबद्धता को बखूबी निभाया। उनके स्नेहपूर्ण स्वभाव और दृढ़ जिम्मेदारी की भावना ने उन्हें शाही परिवार के भीतर और उदयपुर के लोगों के बीच सम्मान दिलाया। शिक्षा राजमाता विजयराज कुमारी के सार्वजनिक जीवन का एक अभिन्न अंग थी। उन्होंने ऊटी के फ्रांसिस्कन कॉन्वेंट स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, जिसने उन्हें आधुनिक दृष्टिकोण प्रदान किया और साथ ही उन्हें मजबूत मूल्यों से भी परिचित कराया।

उदयपुर में बसने के बाद, उन्होंने शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने और महिला सशक्तीकरण के उद्देश्य से शुरू की गई पहलों का समर्थन करने में गहरी रुचि ली। महाराणा मेवाड़ पब्लिक स्कूल (एमएमपीएस) के साथ उनका जुड़ाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो गया। 1980 के दशक के दौरान, उन्होंने संस्था के विकास और परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इसे एक आधुनिक, अनुशासित और गुणवत्ता-केंद्रित शैक्षिक मॉडल की ओर निर्देशित करने में मदद की। संस्था में उनके योगदान का अमिट प्रभाव रहा, जिसके परिणामस्वरूप कई पीढ़ियों के छात्र उच्च शिक्षा और पेशेवर करियर की ओर अग्रसर हुए। जो लोग उन्हें करीब से जानते थे, उनके लिए राजमाता विजयराज कुमारी के लिए शिक्षा केवल एक संस्था निर्माण प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि यह युवाओं के लिए अवसर सृजित करने और उनके भविष्य को संवारने का एक साधन था।

उनकी मृत्यु के बाद, शाही परिवार और प्रशासन ने स्थापित परंपराओं के अनुसार उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था की है। उनकी अंतिम यात्रा उदयपुर के सिटी पैलेस परिसर में स्थित शंभू निवास पैलेस से सुबह रवाना हुई। बड़ी संख्या में नागरिक, सामाजिक संगठनों के सदस्य और गणमान्य व्यक्ति अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए महल में एकत्रित हुए। इसके बाद यात्रा मेवाड़ परिवार के ऐतिहासिक शाही श्मशान घाट, महासतियाजी आहार की ओर बढ़ी। वहां उनके अंतिम संस्कार पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार शाही गार्ड ऑफ ऑनर की उपस्थिति में संपन्न किए जा रहे हैं। उनकी अंतिम यात्रा के दृश्य उदयपुर के लोगों के साथ दशकों से बने उनके गहरे जुड़ाव को दर्शाते हैं। राजमाता विजयराज कुमारी मेवाड़ की स्मृति में शोक सभाओं का आयोजन किया जाएगा। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, ये सभाएं 16 सितंबर से 23 सितंबर तक प्रतिदिन दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे के बीच सिटी पैलेस परिसर में स्थित शंभू निवास पैलेस में आयोजित की जाएंगी। मेवाड़ परिवार से जुड़ी विरासत और परंपराओं की संरक्षक होने के साथ-साथ, शिक्षा और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में उनका कार्य एक दूरदर्शी दृष्टिकोण को दर्शाता था। उदयपुर के लिए, उनका निधन पूर्व शाही परिवार के एक सदस्य की मृत्यु से कहीं अधिक है। यह एक ऐसी महिला का नुकसान है जो कई दशकों में शहर के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने-बाने का अभिन्न अंग बन गई थीं।

घर में रखे फ्रिज में जोरदार धमाके के बाद लगी भीषण आग, एक ही परिवार के 4 लोग जिंदा जले

बेलागावी (एजेंसी)। कर्नाटक के बेलगावी शहर में अग्निकांड में एक ही परिवार के चार सदस्यों की जिंदा जलकर मौत हो गई। हादसे में दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना शहर के चवहत गली इलाके की है और मार्केट पुलिस स्टेशन क्षेत्र में हुई।

जानकारी के अनुसार, परिवार के सदस्य रात के समय घर के अंदर मौजूद थे। इसी दौरान घर में रखे फ्रिज में अचानक धमाका हुआ। धमाके के बाद फ्रिज में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि घर के अंदर मौजूद लोगों को बाहर निकलने का पर्याप्त मौका नहीं मिल सका। कई लोग आग के बीच फंस गए और उनकी मौके पर ही झुलसकर मौत हो गई।

हादसे में मरने वालों की पहचान गजानन डमोने (65), रोशन डमोने (21), शारदा डमोने (45) और भारती राडमोने (50) के रूप में हुई है। वहीं प्रिया डमोने (28) और गंगा डमोने (25) आग की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गईं। दोनों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझाने के बाद घर के अंदर तलाशी ली गई, जिसमें चार लोगों के शव बरामद हुए। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चेन्नई के मदुरावोयाल में डॉ. एम.जी.आर. एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के 36वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया।

राजौरी में आतंकी नेटवर्क पर पुलिस का शिकंजा, लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े तीन ओडीडब्ल्यू गिरफ्तार; आईईडी बरामद

राजौरी (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने राजौरी में आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े ओवर ग्राउंड वर्कर नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी आतंकवादियों को लॉजिस्टिकल सपोर्ट देने, उनकी सुरक्षित आवाजाही में मदद करने और जमीनी स्तर पर अन्य सहायता उपलब्ध कराने में कथित तौर पर शामिल थे।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जाकिर हुसैन पुत्र गुलाम हुसैन निवासी कोटचरवाल टेरियाथ, राजौरी, मोहम्मद आजम पुत्र अली बहादुर निवासी कोटचरवाल टेरियाथ, राजौरी और मोहम्मद मुश्ताक पुत्र मोहम्मद इकबाल निवासी उधान, राजौरी के रूप में हुई है। तीनों आरोपी राजौरी जिले के रहने वाले हैं। पुलिस ने पीर पंजाल इलाके में सक्रिय एक आतंकी मॉड्यूल की जांच के दौरान इन आरोपियों को गिरफ्तार किया। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी कथित तौर पर आतंकवादियों को लॉजिस्टिकल सहायता, सुरक्षित ठिकाने और आवाजाही में मदद मुहैया कराते थे। जांच में यह भी पता चला है कि आरोपी कथित तौर पर गाइड के रूप में काम करते थे और आतंकवादियों को पीर पंजाल क्षेत्र से कश्मीर घाटी की ओर जाने में मदद करते थे। पुलिस को संदेह है कि उन्होंने नागरिकों पर हमलों समेत कई बड़े आतंकी हमलों में शामिल आतंकवादियों को जमीनी स्तर पर सहायता उपलब्ध कराई थी।

जांच के दौरान एक आरोपी की निशानदेही पर भारी मात्रा में आईईडी बरामद की गई। शुरुआती जांच के अनुसार, यह आईईडी कथित तौर पर आतंकी संगठन के सदस्यों ने आरोपी को सुरक्षित रखने के लिए सौंपी थी। पुलिस को आशंका है कि इसका इस्तेमाल किसी लक्षित आतंकी हमले में किया जाना था। पुलिस ने मामले की जांच आगे बढ़ा दी है और गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर आतंकी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान और उनकी भूमिका का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

रिक्त पदों की वजह से ट्रिब्यूनल खत्म नहीं होने चाहिए: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि रिक्त पदों के कारण ट्रिब्यूनल निष्क्रिय नहीं होने चाहिए, और केंद्र सरकार से कहा कि वह नई नियुक्तियां होने तक ऐसे अर्द्ध-न्यायिक निकायों के रिटायर हो रहे पीठासीन अधिकारियों और सदस्यों का कार्यकाल एक महीने या उसके आसपास बढ़ाने पर विचार करे।

इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने की. केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने पीठ से कहा कि नई नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू हो गई है और एड हॉक एक्सटेंशन की ऐसी किसी भी अर्जी पर विचार नहीं किया जाना चाहिए. अटॉर्नी जनरल का जवाब एक वकील की उस बात पर आया जिसमें उन्होंने अलग-अलग ट्रिब्यूनल में खाली पदों के बारे में बताया था, जिसमें डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल भी शामिल है, जिसके कुछ सदस्य जल्द ही रिटायर हो रहे हैं. अटॉर्नी जनरल ने कहा, अब जब सब कुछ शुरू हो गया है, तो इन अंतरिम एप्लीकेशन पर अब और विचार नहीं किया जा सकता है. एक या दो महीने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. पीठ ने अटॉर्नी जनरल से पूछा, क्या आप अपने स्तर पर यह निर्णय ले सकते हैं कि आप एक या दो महीने के लिए एड हॉक व्यवस्था बढ़ाएंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि उसे इस बात का एक निश्चित जवाब चाहिए कि पदों को भरा जाएगा, और आगे जोड़ा कि जैसे ही वह इन याचिकाओं का निपटारा करेगी और अगर कोई नई नियुक्ति नहीं की जाती है, तो (विवाद का) एक और दौर शुरू हो जाएगा. यह तर्क दिया गया कि अब नया ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम, 2026 आ गया है और यह नियुक्ति प्रक्रिया का प्रावधान करता है. सीजेआई ने कहा, हम नहीं चाहते कि ट्रिब्यूनल खत्म हो जाएं. मौजूदा व्यवस्था एड हॉक पर जारी रह सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई तय की है. इस महीने की शुरुआत में, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अलग-अलग ट्रिब्यूनल के 248 सदस्यों को ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम, 2026 के तहत सेवा विस्तार के लिए योग्य पाया गया है और उनकी सेवा बढ़ाई जा रही है.

भारत डिफेंस एक्सपोर्टर बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा आगे : राजनाथ सिंह

नई दिल्ली (एजेंसी) । भारत आज आयातक से रक्षा निर्यातक बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मंगलवार को यह बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कही। उन्होंने बताया कि बीते कुछ वर्षों में स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम भारत में नवाचार के नए ध्वजवाहक बनकर उभरे हैं। यही छोटे उद्यम नए विचारों और नई प्रौद्योगिकियों को जन्म देते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने इनके लिए ऐसा ढांचा तैयार किया है, जिसके माध्यम से स्टार्टअप और एमएसएमई सीधे डीआरडीओ की प्रयोगशालाओं के साथ संवाद कर सकते हैं। डीप टेक व विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में काम करने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नई दिल्ली में आयोजित डीआरडीओ-उद्योग समन्वय बैठक 'विमर्श 2026' में बोल रहे थे। यहां उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में एमएसएमई और स्टार्टअप की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये उद्यम बड़े रक्षा तंत्रों के घटक व उप-तंत्रों से लेकर अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी तक विकसित कर रहे हैं। अब डीआरडीओ व उद्योगों की साझेदारी केवल उत्पादन तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। रिसर्च, डिजाइन, परीक्षण, प्रमाणन और विनिर्माण की पूरी श्रृंखला में साझेदारी बढ़ानी होगी। बड़े उद्योगों के साथ एमएसएमई व स्टार्टअप को भी रक्षा आपूर्ति श्रृंखला का अभिन्न हिस्सा बनाना होगा। रक्षा मंत्री ने कहा, आज डीआरडीओ के पास ज्ञान और प्रौद्योगिकी है, इंडस्ट्री के पास विस्तार और विनिर्माण क्षमता है, स्टार्टअप के पास नवाचार और तेजी से काम करने की क्षमता है और हमारे युवाओं के पास नए भारत का सपना है। जब ये चारों शक्तियां एक साथ आएंगी, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रह जाएगा। जब ये चारों शक्तियां एक दिशा में आगे बढ़ेंगी, तो भारत की रक्षा क्षमता को दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती।

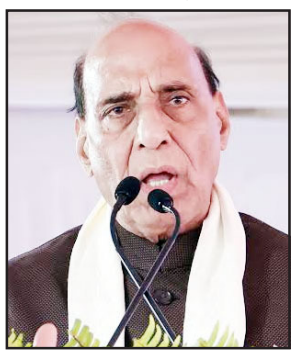

उन्होंने बताया कि आज जारी की गई नई नीतियां और दिशानिर्देश भी उद्योग के लिए नई संभावनाएं लेकर आए हैं। इनका फोकस उद्योग के नेतृत्व वाले रिसर्च एवं डेवलपमेंट, स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के वित्त पोषण को बढ़ावा देना है। शिक्षा जगत और उद्योग के बीच सहयोग व एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग व हाइपरसोनिक जैसी भविष्य की प्रौद्योगिकियों में निवेश को बढ़ावा देने पर फोकस किया गया है।

राजनाथ सिंह ने कहा, रक्षा क्षेत्र में रिसर्च व डेवलपमेंट के लिए डीआरडीओ आज शीर्ष संगठन है। हालांकि, एक सच्चाई यह भी है कि रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए केवल सरकार या डीआरडीओ के प्रयास पर्याप्त नहीं हैं। यह एक सहयोगात्मक प्रयास है। यही सहयोग इस विमर्श 2026 का मुख्य संदेश है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और उद्योग के बीच की साझेदारी ही भारत को रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बना सकती है। कोई भी उत्पाद भारत में विकसित कर देना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है उत्पाद बनाने की क्षमता और आत्मविश्वास विकसित करना। इसलिए हमने कई योजनाएं शुरू कीं, ताकि हम भारत के हर एक शहर, हर एक कस्बे, हर एक गली-कूचे से प्रतिभाओं को सामने ला सकें और पूरा देश एक साथ आत्मनिर्भरता के सुर में सुर मिला सके। और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि हम बहुत हद तक सफल भी हो रहे हैं।

रक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि आत्मनिर्भरता का मतलब केवल कुछ कलपुर्जे, कुछ मिसाइल, कुछ हथियार उपकरण विकसित करना नहीं है। उन्होंने कहा, आत्मनिर्भरता हमारे चरित्र का हिस्सा होना चाहिए। हमारे रवैये का हिस्सा होना चाहिए। जिस देश के पास अपनी प्रौद्योगिकी है, उसके पास अपना भविष्य तय करने की ताकत भी है। इसलिए हमारी आत्मा में, हमारे मन में, हमारे विचार में, हमारी चेतना में आत्मनिर्भरता का भाव होना चाहिए। अभी पिछले कुछ वर्षों में हमने रक्षा क्षेत्र में जो सुधार देखे हैं, वे अभूतपूर्व हैं।उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण और नेतृत्व में हमने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। चाहे वह सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची हो, 'मेक इन इंडिया' पहल हो, आईडेक्स हो, अदिति हो, या फिर रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का 25 प्रतिशत निजी क्षेत्र के लिए आवंटित करने का फैसला हो, ये सब कुछ आपने देखा है, महसूस किया है। हमने वह सब किया, जिससे हम यह सुनिश्चित कर सकें कि हम रक्षा क्षेत्र में आयात पर निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे। मंगलवार को आयोजित इस कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण नीतियां और दिशानिर्देश भी जारी हुए हैं। कई महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों का भी आदान-प्रदान हुआ है। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और अनुबंधों का हस्तांतरण भी इसी क्रम में हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट से एनएसई की पूर्व एमडी चित्रा रामकृष्ण को बड़ा झटका

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की पूर्व पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ चित्रा रामकृष्ण की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया है. चित्रा रामकृष्ण ने खुद को गैर सरकारी कर्मचारी बताते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई को चुनौती दी थी.

जस्टिस जेबी पारदीवाला और के विनोद चंद्रन की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से मना कर दिया. अदालत ने कहा कि उनका मानना है कि हाई कोर्ट ने विवादित फैसला सुनाने में कोई गलती नहीं की है. याचिकाकर्ता एनएसई की एमडी और सीईओ थीं. तर्क यह है कि एनएसई एक प्राइवेट/गैर-सरकारी कंपनी है. इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता कोई सरकारी काम कर रही थीं. ऐसे में कोर्ट मानना है कि यह मुद्दा ट्रायल के दौरान उठाया जा सकता है. इस मुद्दे पर ट्रायल कोर्ट को अपने हिसाब से फैसला करने दें.

लॉरेंस गैंग के करीबी कर्मवीर देओ पर पंजाब पुलिस का शिकंजा

कनाडा से डिपोर्ट होकर दिल्ली पहुंचते ही गिरफ्तार

नई दिल्ली (एजेंसी)। कनाडा से भारत डिपोर्ट किए गए गैंगस्टर कर्मवीर देओ को पंजाब पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है। कर्मवीर को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का करीबी बताया जाता है। आरोप है कि वह विदेश में रहकर गैंग के सदस्यों को पनाह और अन्य तरह की मदद मुहैया कराता था। पंजाब पुलिस ने उसके खिलाफ पहले ही लुकआउट सर्कुलर जारी किया हुआ था। कनाडा से भारत पहुंचते ही पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया।

कर्मवीर देओ पर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को भारत से फरार होने में मदद करने का आरोप है। बताया जाता है कि अनमोल अमेरिका में कर्मवीर के घर पर भी रुका था। अनमोल का अमेरिका में पंजाबी गायकों के साथ डांस और पार्टी करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था। दावा किया गया था कि यह वीडियो कर्मवीर के घर का है। इसके बाद अनमोल को पनाह देने में कर्मवीर की भूमिका को लेकर भी सवाल उठे थे।

आरोप है कि कर्मवीर की भूमिका केवल अनमोल बिश्नोई को अपने घर पर ठहराने तक सीमित नहीं थी। बताया जाता है कि अमेरिका पहुंचने वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्यों को वह शेल्टर उपलब्ध कराता था। इसके अलावा गैंग से जुड़े लोगों को कानूनी मदद मुहैया कराने में भी उसकी भूमिका बताई जाती है। जांच एजेंसियां विदेश में गैंग के सदस्यों के लिए ठहरने और कानूनी सहायता की व्यवस्था करने में उसकी कथित भूमिका की जांच कर सकती हैं।

भारत शांति, प्रगति और समृद्धि की सशक्त आवाज के रूप में उभर रहा : उपराष्ट्रपति

सीपी राधाकृष्णन ने आईसीडब्ल्यूए के राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में 25 वर्ष पूरे होने पर आयोजित समारोह को किया संबोधित

नई दिल्ली (एजेंसी)। उपराष्ट्रपति और भारतीय वैश्विक परिषद (आईसीडब्ल्यूए) के अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि मानव प्रगति और विश्व शांति तभी संभव है, जब सभी राष्ट्र एक-दूसरे की चिंताओं को समझें और पारस्परिक लाभ के लिए मिलकर काम करें। उन्होंने कहा कि कूटनीति का पहला उद्देश्य राष्ट्रों के बीच अच्छे संबंध स्थापित करना है और मानव प्रगति तथा विश्व शांति को साथ-साथ आगे बढ़ना चाहिए।

उपराष्ट्रपति नई दिल्ली स्थित सप्रू हाउस में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में भारतीय वैश्विक परिषद (आईसीडब्ल्यूए) के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित रजत जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह अवसर परिषद की उपलब्धियों के लिए आभार व्यक्त करने और आत्मचिंतन करने का भी है। उन्होंने आईसीडब्ल्यूए की उत्कृष्ट विरासत में योगदान देने वाले संस्थापकों, पूर्व नेतृत्वकर्ताओं, महानिदेशकों, विद्वानों, राजनयिकों, शोधकर्ताओं और कर्मचारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

सीपी राधाकृष्णन ने भारत में सफलतापूर्वक आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए विदेश मंत्री और आईसीडब्ल्यूए के उपाध्यक्ष डॉ. एस. जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिसरी तथा विदेश मंत्रालय की पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि संघर्षों और विरोधाभासों से घिरी दुनिया में नई दिल्ली नेताओं की घोषणा को सर्वसम्मति से अपनाया जाना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में संवाद, सहयोग और आपसी समझ को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है। राष्ट्रों के बीच विश्वास और बेहतर संबंधों के माध्यम से ही वैश्विक शांति और स्थायी विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत शांति, प्रगति और समृद्धि की एक सशक्त आवाज के रूप में उभर रहा है। उन्होंने 'वसुधैव कुटुंबकम' यानी 'विश्व एक परिवार है' की भावना को भारत की विदेश नीति और वैश्विक सहभागिता का महत्वपूर्ण आधार बताया। उन्होंने कोविड संकट के दौरान भारत की 'वैक्सीन मैत्री', आपदा के समय किए गए राहत एवं प्रतिक्रिया प्रयासों, पर्यावरण के लिए जीवन शैली (एलआईएफई), अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जैसी पहलों को इस दर्शन के व्यावहारिक उदाहरण बताया। उपराष्ट्रपति ने यूपीआई और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पारदर्शी भुगतान प्रणालियां पारदर्शी शासन व्यवस्था की दिशा में योगदान करती हैं। भारत आईटीईसी और शैक्षिक सहयोग के माध्यम से वैश्विक दक्षिण के देशों के साथ अपनी तकनीकी और संस्थागत क्षमताएं साझा कर रहा है। उन्होंने ज़ांज़ीबार में भारत के बाहर स्थापित आईआईटी परिसर का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत की क्षमताओं और अनुभवों का लाभ दूसरे देशों तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक दक्षिण के नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ रहा है और अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के बीच भारत के प्रति विश्वास एवं भरोसा लगातार बढ़ रहा है।

सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि बदलते वैश्विक परिवेश में भारतीय वैश्विक परिषद की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। उन्होंने परिषद के लिए चार प्रमुख प्राथमिकताएं निर्धारित कीं।

पहली प्राथमिकता भारत की 'पड़ोसी प्रथम', 'एक्ट ईस्ट', 'वैश्विक दक्षिण' और 'हिंद-प्रशांत' प्राथमिकताओं से संबंधित अनुसंधान को मजबूत करना है। दूसरी प्राथमिकता साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं से संबंधित कार्यों का विस्तार करना है।

तीसरी प्राथमिकता विश्वविद्यालयों और युवा विद्वानों के साथ सहभागिता को और मजबूत करना तथा चौथी प्राथमिकता विश्व मामलों से संबंधित ज्ञान के एक विश्वसनीय भंडार के रूप में विकसित होना है, जिसमें भारत का प्रामाणिक दृष्टिकोण प्रतिबिंबित हो। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आईसीडब्ल्यूए को 'विकसित भारत@2047' के लिए बौद्धिक और संस्थागत रूप से स्वयं को तैयार करना चाहिए। उन्होंने परिषद से अंतरराष्ट्रीय मामलों के अध्ययन के लिए दुनिया के सम्मानित केंद्रों में से एक बनने की दिशा में काम करने का आह्वान किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आईसीडब्ल्यूए अपनी स्वर्ण जयंती तक भारत और एक शांतिपूर्ण विश्व व्यवस्था के निर्माण में और अधिक महत्वपूर्ण योगदान देगा। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति ने आईसीडब्ल्यूए की यात्रा और विकास को दर्शाने वाली फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने परिषद में योगदान के सम्मान में पूर्व महानिदेशकों को स्मृति-चिह्न भी प्रदान किए।

स्टीव स्मिथ ने टेस्ट संन्यास को लेकर दिया बड़ा संकेत, एशेज खेलने पर भी संशय

लंदन (एजेंसी)। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने टेस्ट क्रिकेट में अपने भविष्य को लेकर बड़ा संकेत दिया है। 37 वर्षीय स्मिथ ने अगले साल इंग्लैंड में होने वाली एशेज सीरीज में खेलने को लेकर अनिश्चितता जताई है। उन्होंने साफ किया कि वह अपने टेस्ट करियर को सीरीज-दर-सीरीज आधार पर देख रहे हैं।

स्मिथ इस समय दुनिया के दूसरे नंबर के टेस्ट बल्लेबाज हैं। उनसे आगे इंग्लैंड के हैरी ब्रूक हैं। स्मिथ ने 125 टेस्ट मैचों में 37 शतक लगाए हैं और ऑस्ट्रेलिया के लिए लंबे समय से बल्लेबाजी की रीढ़ बने हुए हैं। 'द टेलीग्राफ' से बातचीत में स्टीव स्मिथ ने कहा कि इंग्लैंड की धरती पर एशेज सीरीज जीतना उनकी अधूरी इच्छा है, लेकिन अगले साल के दौरे में शामिल होने का फैसला अभी तय नहीं है। स्मिथ ने कहा, 'मुझे खुद नहीं पता कि मैं वहां रहूंगा या नहीं। मैं पिछले कुछ समय से सीरीज-दर-सीरीज के आधार पर आगे बढ़ रहा हूं और फिलहाल मेरे लिए यह दौरा अभी काफी दूर है। मैं वहां एशेज जीतना चाहता हूं या कम से कम जीत चुका होना चाहता हूं, लेकिन अब देखना होगा कि ऐसा हो पाता है या नहीं।'

स्टीव स्मिथ का एशेज रिकॉर्ड शानदार रहा है। उन्होंने इंग्लैंड की धरती पर एशेज मुकाबलों में सात शतक लगाए हैं। इसके बावजूद इंग्लैंड और भारत में टेस्ट सीरीज जीतना उनके करियर की उन उपलब्धियों में शामिल है, जो अभी तक पूरी नहीं हो सकी हैं। स्मिथ ने 125 टेस्ट मैचों में 10,920 रन बनाए हैं। उनका बल्लेबाजी औसत करीब 56 का है। 37 टेस्ट शतकों के साथ वह ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में रिकी पोंटिंग के बाद सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं।

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सामने अगले एक साल में 18 टेस्ट मैचों का बेहद व्यस्त कार्यक्रम है। इस दौरान विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी हो सकता है। ऐसे में अगर स्मिथ इस लंबे कार्यक्रम से पहले टेस्ट क्रिकेट से दूरी बनाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के मध्यक्रम पर बड़ा असर पड़ सकता है।

मार्नस लाबुशेन की हालिया खराब फॉर्म और घरेलू क्रिकेट में अनुभवी टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों की कमी के कारण स्मिथ का विकल्प तलाशना ऑस्ट्रेलिया के लिए आसान नहीं होगा। स्मिथ का ध्यान अब टेस्ट क्रिकेट से ज्यादा टी20 प्रारूप की ओर जाता दिखाई दे रहा है। वह 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए वह दुनिया की अलग-अलग फ्रेंचाइजी टी20 लीग में खेलकर अपने छोटे प्रारूप के कौशल को मजबूत कर रहे हैं।

स्मिथ ने आखिरी बार फरवरी 2024 में ऑस्ट्रेलिया के लिए टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला था। उनका मानना है कि ओलंपिक टीम में जगह बनाना उनके करियर का सबसे बड़ा मौजूदा लक्ष्य है। स्मिथ ने कहा, 'फिलहाल मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य ओलंपिक में हिस्सा लेना है। मैं ऑस्ट्रेलिया की टीम में जगह बनाने की कोशिश करना चाहता हूं। एम्स्टर्डम में खेलने का एक कारण यह भी था कि मैं ज्यादा से ज्यादा टी20 क्रिकेट खेलता रहूं।'

इस बयान से संकेत मिलता है कि स्मिथ अपने करियर के अगले चरण में टेस्ट क्रिकेट के बजाय टी20 क्रिकेट और ओलंपिक में भागीदारी को प्राथमिकता दे सकते हैं। हालांकि, उन्होंने अभी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की आधिकारिक घोषणा नहीं की है।

इमरान खान के समर्थन में ऑस्ट्रेलिया के सात पूर्व कप्तानों की मानवीय अपील, विदेश मंत्री को लिखा पत्र

नई दिल्ली (एजेंसी)। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट कप्तान और प्रधानमंत्री इमरान खान की हिरासत और स्वास्थ्य को लेकर ऑस्ट्रेलिया के सात पूर्व क्रिकेट कप्तानों ने मानवीय चिंता जताई है। इन पूर्व खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग से संपर्क कर इमरान खान के साथ हो रहे व्यवहार पर ध्यान देने की अपील की है।

विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग को भेजे गए पत्र पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान एलन बॉर्डर, ग्रेग चैपल, इयान चैपल, बेलिंडा क्लार्क, किम ह्यूजेस, मार्क टेलर और स्टीव वॉ ने हस्ताक्षर किए हैं। पूर्व कप्तानों ने स्पष्ट किया कि उन्होंने यह पत्र 'राजनयिकों या राजनीतिक हस्तियों के रूप में नहीं, बल्कि पूर्व कप्तानों के रूप में लिखा है, जिन्हें अपनी बात रखने की जरूरत महसूस हुई।'

पत्र में पूर्व क्रिकेटरों ने कहा कि वे इमरान खान के खिलाफ चल रहे कानूनी या राजनीतिक मामलों पर कोई राय नहीं दे रहे हैं। उनके मुताबिक, यह पाकिस्तान का आंतरिक मामला है। हालांकि, उन्होंने हिरासत में रखे गए किसी भी व्यक्ति के साथ होने वाले व्यवहार को लेकर चिंता जताई। पूर्व कप्तानों ने इसे 'राजनीति चाहे जो भी हो, बुनियादी इंसानियत का मामला' बताया।

नवीनतम पत्र में कहा गया है कि इमरान खान के बेटे और बहनें कई महीनों से सार्वजनिक रूप से उनकी सेहत और हिरासत में उनके साथ किए जा रहे व्यवहार पर चिंता जाहिर कर रहे हैं। इन चिंताओं में सीमित चिकित्सा सुविधाएं, परिवार से मिलने पर रोक और कानूनी सलाह लेने की सीमित सुविधा शामिल हैं। इससे पहले 23 अगस्त को दुनिया के 22 पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कप्तानों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पत्र लिखा था। इस पत्र में इमरान खान के बेहतर इलाज की मांग की गई थी। पूर्व कप्तानों का कहना था कि इमरान खान को मिल रही चिकित्सा सुविधा पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप नहीं है। उस पत्र में तीन प्रमुख मांगें रखी गई थीं।

पूर्व कप्तानों ने मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित मेडिकल बोर्ड को इमरान खान की सेहत की पूरी और स्वतंत्र जांच करने की अनुमति दी जाए। इस बोर्ड में इमरान के निजी डॉक्टरों को भी शामिल किया जाना था। विशेष रूप से उनकी दाहिनी आंख की रोशनी कम होने की खबरों की जांच करने की मांग की गई थी।

बाबर आजम की सात साल बाद घरेलू क्रिकेट में वापसी

नई दिल्ली (एजेंसी)। पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम करीब सात साल बाद घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट में वापसी करने जा रहे हैं। पाकिस्तान की टेस्ट टीम के खराब प्रदर्शन और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में बिगड़ती स्थिति के बीच बाबर का यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है।

बाबर ने आखिरी बार दिसंबर 2019 में घरेलू रेड-बॉल क्रिकेट खेला था। अब वह एक बार फिर पाकिस्तान के घरेलू मैदान पर लंबे प्रारूप में नजर आएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक, बाबर आजम ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड की टीम का हिस्सा होंगे। वह 16 सितंबर को इंग्लैंड से पाकिस्तान लौटने की उम्मीद है और इसके अगले दिन टीम के साथ जुड़ सकते हैं। OGDCL की स्पोर्ट्स हेड फराह बतूल ने द डॉन से पुष्टि की कि बाबर के लिए किट पहले ही ऑर्डर की जा चुकी है। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि वह प्रतियोगिता का दूसरा मुकाबला खेलेंगे या तीसरा।

महिला एशिया कप

चरणी ने रचा इतिहास, 800 रेटिंग अंक पार करने वाली पहली भारतीय गेंदबाज बनीं

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत की महिला टीम ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर महिला एशिया कप 2026 का खिताब अपने नाम किया। यह भारत का रिकॉर्ड आठवां एशिया कप खिताब रहा। इस शानदार प्रदर्शन का असर अब आईसीसी महिला टी20 प्लेयर रैंकिंग में भी देखने को मिल रहा है, जहां भारतीय खिलाड़ियों ने बड़ी छलांग लगाई है।

भारत की बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज चरणी ने एशिया कप के फाइनल में चार विकेट हासिल किए। पूरे टूर्नामेंट में उनके नाम 12 विकेट रहे। इस प्रदर्शन के दम पर वह टी20 गेंदबाजों की रैंकिंग में 802 रेटिंग अंकों के साथ शीर्ष पर अपनी स्थिति और मजबूत करने में सफल रही हैं।

चरणी 800 रेटिंग अंक का आंकड़ा पार करने वाली पहली भारतीय गेंदबाज बन गई हैं। वह महिला टी20 गेंदबाजों की रैंकिंग में इस खास उपलब्धि को हासिल करने वाली दुनिया की चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हो गई हैं। चरणी से ज्यादा रेटिंग अंक केवल ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाज मेगन शुट के नाम हैं, जिनके खाते में 806 अंक हैं। इंग्लैंड की स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन भी 802 रेटिंग अंकों के साथ चरणी के बराबर हैं।

दीप्ति शर्मा ने भी लगाई बड़ी छलांग

भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने भी रैंकिंग में शानदार सुधार किया है। एशिया कप में 14 विकेट लेने वाली दीप्ति चार स्थान की छलांग लगाकर टी20 गेंदबाजों की रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गई हैं। फाइनल मुकाबले में दीप्ति ने 3/19 का शानदार स्पेल किया था। उनके बेहतरीन प्रदर्शन ने भारत की खिताबी जीत में अहम भूमिका निभाई।

बल्लेबाजी रैंकिंग में भी शफाली वर्मा का जलवा

टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में शफाली वर्मा को भी फायदा हुआ है। एशिया कप में सबसे ज्यादा 236 रन बनाने वाली शफाली एक स्थान ऊपर उठकर छठे नंबर पर पहुंच गई हैं। टूर्नामेंट में उनका बल्लेबाजी औसत 47.20 रहा। शफाली ने ऑलराउंडरों की रैंकिंग में भी पांच स्थान की छलांग लगाई है। वह अब इस सूची में 15वें स्थान पर पहुंच गई हैं।

भुवनेश्वर कुमार ने बताया टीम इंडिया से बाहर होने का दर्द, बोले- 'यह आसान नहीं था'

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय टीम से लंबे समय से बाहर चल रहे अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर के अंत को स्वीकार करने के दर्द पर खुलकर बात की है। भुवनेश्वर की भारत के लिए दोबारा खेलने की इच्छा अभी भी बनी हुई है, लेकिन अब वह चयनकर्ताओं के फैसलों पर अपनी मानसिक शांति निर्भर नहीं रखते। अगर उन्हें दोबारा टीम इंडिया में जगह नहीं मिलती है, तो अब वह इसे पहले की तरह व्यक्तिगत झटके के तौर पर नहीं देखते।

2026 आईपीएल सीजन के बाद भुवनेश्वर कुमार की भारतीय टीम में वापसी की मांग और तेज हो गई। उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को लगातार दो आईपीएल खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई। आरसीबी की 2025 की पहली खिताबी जीत में भुवनेश्वर ने 17 विकेट लिए थे। इसके बाद 2026 सीजन में उन्होंने 28 विकेट चटकाए और पर्पल कैप जीतने से सिर्फ एक विकेट दूर रह गए।

भुवनेश्वर ने घरेलू क्रिकेट में भी अपनी शानदार फॉर्म जारी रखी। उन्होंने लखनऊ फाल्कन्स की कप्तानी करते हुए टीम को यूपी टी20 लीग के फाइनल तक पहुंचाया। सेमीफाइनल में उन्होंने केवल 10 रन देकर चार विकेट हासिल किए। इस प्रदर्शन ने एक बार फिर साबित किया कि भुवनेश्वर कुमार की गेंदबाजी में अब भी बड़े स्तर पर प्रभाव छोड़ने की क्षमता मौजूद है।

जतिन सप्रु के यूट्यूब पॉडकास्ट पर बातचीत के दौरान भुवनेश्वर कुमार ने नवंबर 2022 के बाद टीम इंडिया से दूर होने के अनुभव को साझा किया। उन्होंने बताया, 'टीम मैनेजमेंट से हुई निजी बातचीत के आधार पर मुझे लगा था कि भारत के लिए खेलने के कुछ और मौके मिलेंगे। हालांकि, जब वे मौके नहीं आए, तो मुझे धीरे-धीरे समझ आ गया कि मेरा अंतरराष्ट्रीय करियर उम्मीद से काफी पहले खत्म हो चुका है।' भुवनेश्वर ने कहा, 'इस मुश्किल दौर से बाहर निकलने में मेरे परिवार ने बड़ी भूमिका निभाई।'

भुवनेश्वर कुमार ने बताया कि 2022 टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ भारत की हार के बाद उन्हें अंदाजा हो गया था कि अब टीम में बदलाव का दौर शुरू होगा। एडिलेड में हार के बाद जब ड्रेसिंग रूम का माहौल बेहद निराशाजनक था, तब भुवनेश्वर अपने होटल के कमरे में लौटे और अपनी पत्नी नूपुर से कहा कि यह उनका आखिरी वर्ल्ड कप था। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर समझा था कि किसी बड़े टूर्नामेंट में हार के बाद चयनकर्ता भविष्य को ध्यान में रखते हुए युवा खिलाड़ियों को मौका देना शुरू कर देते हैं।

भुवनेश्वर कुमार ने कहा, 'कुछ और सीरीज तक। क्योंकि मुझे एक कॉल आया था। उन्होंने जो कहा, उसके आधार पर मुझे लगा कि शायद अगली दो सीरीज में मौका मिल सकता है। यह आसान नहीं था, लेकिन परिवार ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई।' उन्होंने आगे कहा, 'एडिलेड में ऐसा हुआ। मैं अपने कमरे में आया और अपनी पत्नी से कहा। मैंने यह बात अपने अनुभव के आधार पर कही थी। ड्रेसिंग रूम में हर कोई निराश था। जाने से पहले कुछ बातचीत हुई थी। लेकिन जब मैं कमरे में वापस आया, तो मैंने अपनी पत्नी नूपुर से कहा कि यह मेरा आखिरी वर्ल्ड कप है।' भुवनेश्वर ने चयन प्रक्रिया को लेकर कहा, 'मेरे अनुभव के अनुसार, जब आप इस तरह का कोई टूर्नामेंट हारते हैं, तो चयनकर्ता आगे की ओर देखना चाहते हैं और यह सही भी है।'

महिला जूनियर एशिया कप

भारत ने पाकिस्तान को 19-0 से रौंदा, सेमीफाइनल में बनाई जगह

मोकी (एजेंसी)। भारत ने महिला जूनियर एशिया कप 2026 में पाकिस्तान के खिलाफ एकतरफा मुकाबले में 19-0 की शानदार जीत दर्ज की। क्रिकेट में पाकिस्तान को हराने के कुछ ही दिनों बाद भारतीय महिला हॉकी टीम ने भी अपने पड़ोसी प्रतिद्वंद्वी को करारी शिकस्त दी। इस जीत के साथ गत चैंपियन भारत ने टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली।

चीन के मोकी में खेले गए इस मुकाबले में भारतीय टीम ने शुरुआत से ही पाकिस्तान पर दबाव बनाए रखा। भारत ने लगातार गोल दागते हुए मुकाबले को पूरी तरह एकतरफा बना दिया। भारत की ओर से पूजा साहू ने सातवें मिनट में पहला गोल किया। इसके दो मिनट बाद रोशनी ऐंद ने शानदार गोल कर टीम की बढ़त को 2-0 कर दिया। रोशनी ने मुकाबले में दो गोल किए। उनका दूसरा गोल 60वें मिनट के बाद आया।

भारत ने शुरुआती मिनटों में ही पाकिस्तान की रक्षापंक्ति को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया। 11वें मिनट में तनुदिनेश काडू ने गोल किया, जबकि इसके केवल दो मिनट बाद सुखवीर कौर ने भारत की बढ़त बढ़ा दी। इसके बाद 16वें मिनट में मधु सिदार ने गोल किया। 18वें मिनट में गीता यादव ने स्कोर 6-0 कर दिया। 23वें मिनट में सानिका चंद्रकांत माने ने अपना पहला गोल किया और भारत को 7-0 की बढ़त दिलाई। 25वें मिनट में तनुजा टोप्पो ने भारत के लिए एक और गोल किया। इसके दो मिनट बाद पूजा मलिका ने अपना पहला गोल दागा। पूजा मलिका ने मुकाबले में कुल तीन गोल किए और वह मैच की सबसे सफल स्कोरर रहीं। उनके अन्य दो गोल 49वें और 51वें मिनट में आए। 33वें मिनट में पूर्णिमा यादव ने गोल किया, जबकि 39वें मिनट में मधु सिदार ने अपना दूसरा गोल दागा। इस तरह हाफ टाइम तक भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी बढ़त बना ली थी।

दूसरे हाफ में भी भारत ने अपनी रफ्तार कम नहीं की। 40वें मिनट में सुप्रिया ने गोल किया। इसके बाद 48वें मिनट में कृष्णा शर्मा और 49वें मिनट में पूजा मलिका ने गोल किया। 51वें मिनट में पूजा मलिका ने अपना तीसरा गोल पूरा किया। 54वें मिनट में सुप्रिया ने दूसरा गोल किया, जबकि 55वें मिनट में बिनीमा धन ने भारत के खाते में एक और गोल जोड़ा। रोशनी ऐंद ने 60वें मिनट के बाद अपना दूसरा गोल कर भारत का स्कोर 19-0 कर दिया। भारतीय टीम ने पूरे मुकाबले में पाकिस्तान को वापसी का कोई मौका नहीं दिया।

इस जीत के साथ भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला जूनियर एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत इससे पहले जापान, मलेशिया और दक्षिण कोरिया को हराकर तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा था। अब सेमीफाइनल में भारत का सामना दक्षिण कोरिया और मलेशिया के बीच होने वाले क्वार्टरफाइनल मुकाबले के विजेता से होगा।

क्रिकेट के बाद हॉकी में भी पाकिस्तान पर बड़ी जीत

भारत की हॉकी टीम की यह जीत ऐसे समय आई है, जब कुछ दिन पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दुबई में पाकिस्तान को सात विकेट से हराया था।

भारत ने उस मुकाबले में 55 रन के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया था। क्रिकेट और हॉकी, दोनों में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय महिला खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन ने खेल प्रशंसकों का उत्साह और बढ़ा दिया है।

नेपाल प्रीमियर लीग में डेविड वॉर्नर की एंट्री, सीजन 3 के लिए काठमांडू गोर्खाज में शामिल

नई दिल्ली (एजेंसी)। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज डेविड वॉर्नर नेपाल प्रीमियर लीग के तीसरे सीजन में काठमांडू गोर्खाज की ओर से खेलते नजर आएंगे। फ्रेंचाइजी ने वॉर्नर के टीम से जुड़ने की घोषणा की। वॉर्नर ने भी वीडियो संदेश के जरिए नेपाल आने और टीम का हिस्सा बनने को लेकर उत्साह जाहिर किया।

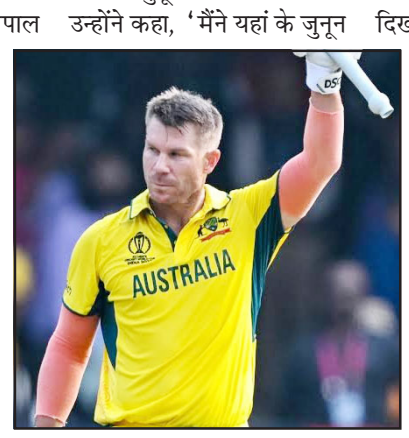

डेविड वॉर्नर ने नेपाल की फ्रेंचाइजी काठमांडू गोर्खाज की ओर से जारी वीडियो में कहा, 'सभी को नमस्कार। मैं नेपाल आने और काठमांडू गोर्खाज की टीम से जुड़ने को लेकर बेहद उत्साहित हूं। मुझे पता है कि बहुत से लोगों के लिए यह बेहद कठिन समय रहा है। मुझे उम्मीद है कि नेपाल प्रीमियर लीग लोगों के चेहरों पर खुशी ला सकेगी और उन्हें एक साथ आने का मौका देगी।'

वॉर्नर ने नेपाल के क्रिकेट फैंस के जुनून की भी तारीफ की। उन्होंने कहा, 'मैंने यहां के जुनून और प्रशंसकों के बारे में बहुत कुछ सुना है। मैं इसका अनुभव करने, आप सभी से मिलने और अपनी टीम के साथ मैदान पर उतरने का इंतजार नहीं कर सकता। तीन शहर, एक आत्मा, एक टीम और एक सपना। आयो गोर्खाली!' फ्रेंचाइजी ने वॉर्नर के टीम में शामिल होने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उत्साह जाहिर किया। काठमांडू गोर्खाज ने लिखा, '12th वॉरियर्स, आपने इसे सच कर दिखाया। दो बार आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप चैंपियन। टी20 विश्व कप चैंपियन और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप विजेता। तिहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज। और आईपीएल में तीन ऑरेंज कैप जीतने वाले इकलौते खिलाड़ी।' फ्रेंचाइजी ने आगे लिखा, 'विश्व क्रिकेट के सबसे विस्फोटक नामों में से एक अब हमारी घाटी में आ रहा है। यह हमारे 12th वॉरियर्स और नेपाल क्रिकेट के लिए है। डेविड वॉर्नर, घाटी में आपका स्वागत है।'

डेविड वॉर्नर आईपीएल इतिहास के सबसे सफल विदेशी बल्लेबाजों में शामिल हैं। उन्होंने भारतीय टी20 लीग में 184 मुकाबलों में 6,565 रन बनाए हैं। वह आईपीएल में विदेशी खिलाड़ियों के बीच सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। वॉर्नर उन चुनिंदा चार खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिन्होंने आईपीएल में 6,000 से ज्यादा रन बनाए हैं। उन्होंने अपने आईपीएल करियर के दौरान दिल्ली कैपिटल्स का प्रतिनिधित्व किया। इसके अलावा, वह 2016 में सनराइजर्स हैदराबाद के साथ आईपीएल खिताब भी जीत चुके हैं। वॉर्नर को आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी में किसी टीम ने नहीं खरीदा था। इसके बाद उन्होंने आईपीएल 2026 के लिए भी अपना नाम पंजीकृत नहीं कराया। हालांकि, फ्रेंचाइजी क्रिकेट में उनकी मांग अब भी बनी हुई है। वॉर्नर हाल के समय में कई टी20 लीग में नजर आए हैं। वह बिग बैश लीग 2025/26 और पाकिस्तान सुपर लीग 2026 में भी खेल चुके हैं। इससे पहले वह दुनिया की कई प्रमुख फ्रेंचाइजी लीग का हिस्सा रहे हैं। काठमांडू गोर्खाज के कार्यकारी निदेशक अनुभव स्वर सिरोहिया ने वॉर्नर के साथ करार को बेहद खास बताया। उन्होंने कहा, 'यह पल मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भी बेहद खास है।' उन्होंने आगे कहा, 'डेविड वॉर्नर को काठमांडू गोर्खाज में लाना रातोंरात संभव नहीं हुआ। इसके लिए कई महीनों तक बातचीत, लगातार प्रयास और सभी लोगों के विश्वास की जरूरत पड़ी। कई मौकों पर यह मुश्किल लगा, लेकिन वॉर्नर जैसे कद के खिलाड़ी को काठमांडू का प्रतिनिधित्व करते हुए टीयू क्रिकेट ग्राउंड पर खेलते देखने की संभावना ने हर प्रयास को सार्थक बना दिया।'

नेपाल क्रिकेट के विकास में योगदान की उम्मीद

सिरोहिया ने कहा कि वॉर्नर का टीम में शामिल होना केवल एक फ्रेंचाइजी के लिए उपलब्धि नहीं है। उन्होंने कहा, 'यह सिर्फ एक खिलाड़ी या एक फ्रेंचाइजी के साथ करार से कहीं बड़ा है। अगर डेविड वॉर्नर जैसे वैश्विक सितारे को नेपाल लाने से युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलती है, समर्थकों में उत्साह बढ़ता है, नेपाल क्रिकेट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक ध्यान मिलता है और नेपाली क्रिकेट के विकास में किसी भी तरह का योगदान होता है, तो यह मेरे लिए सबसे सार्थक उपलब्धियों में से एक होगा। उन्होंने अंत में कहा, 'यह नेपाली क्रिकेट के लिए है। और सबसे बढ़कर, यह नेपाल के उन सभी क्रिकेट प्रशंसकों के लिए है, जिन्हें हमेशा विश्वास रहा है कि हमारा देश और हमारा खेल सबसे बड़े मंच के हकदार हैं।'

एशियन गेम्स से बाहर होने के बाद छलका अनुष अग्रवाला का दर्द, चयन प्रक्रिया पर उठाए सवाल

नई दिल्ली (एजेंसी)।

भारत के ड्रेसाज राइडर और 2022 हांगझोउ एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट अनुष अग्रवाला ने 2026 एशियन गेम्स के लिए चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। टीम में जगह नहीं मिलने के बाद अनुष ने इसे खेल में मिली हार के बजाय 'विश्वासघात' जैसा बताया है।

25 वर्षीय अनुष 2022 हांगझोउ एशियन गेम्स में ऐतिहासिक गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय ड्रेसाज टीम का हिस्सा थे। उन्होंने इसी प्रतियोगिता में व्यक्तिगत ब्रॉन्ज मेडल भी हासिल किया था। इसके अलावा वह 2024 पेरिस ओलंपिक में भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अनुष को जून में इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया की एडहॉक कमेटी ने पहली रिजर्व खिलाड़ी के रूप में चुना था। हालांकि, अंतिम चार सदस्यीय टीम में उन्हें जगह नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने चयन प्रक्रिया को लेकर अपनी नाराजगी सार्वजनिक की। अनुष ने कहा कि वह मैदान पर हार स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि हार-जीत खेल का हिस्सा है। लेकिन उन्हें इस बात का दुख है कि उन्हें मुकाबला करने का मौका ही नहीं दिया गया। उन्होंने लिखा, 'आप संघर्ष करते हैं, जीतते हैं, हारते हैं और फिर पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापसी करते हैं। लेकिन यह हार से कम और विश्वासघात जैसा ज्यादा महसूस हो रहा है।' अनुष ने स्पष्ट किया कि उन्हें दुख प्रतियोगिता में हारने का नहीं, बल्कि प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का अवसर नहीं मिलने का है। उन्होंने कहा, 'मैं इसलिए गहराई से आहत हूं क्योंकि मैं प्रतियोगिता में हारा नहीं, बल्कि मुझे प्रतियोगिता करने का मौका ही नहीं दिया गया।'

संपादकीय

सोनिया का इनकार काबिल-ए-तारीफ निर्णय

सोनिया गांधी अपने अनुभव सुनाना चाहती हैं, तो आखिर उसका अवसर उन्हें क्यों नहीं मिलना चाहिए? अगर उनकी टिप्पणियां पूर्वाग्रह भरी हुईं, तो उनसे आहत पक्ष के पास जवाब देने का पूरा अवसर मौजूद रहेगा।

कहने को तो भारत लोकतंत्र है, लेकिन यहां विपक्ष के सर्व-प्रमुख नेताओं तक को अपनी कहानी बताने की आजादी नहीं है! सोनिया गांधी नरेंद्र मोदी या आरएसएस के बारे में अपने अनुभव या अपनी राय सुनाना चाहती हैं, तो आखिर उसका अवसर उन्हें क्यों नहीं मिलना चाहिए? भारत- चीन संबंध से जुड़ी किसी घटना पर उनकी राय को देश के सामने आने से क्यों रोका जाना चाहिए? अगर उनकी टिप्पणियां पूर्वाग्रह भरी होंगी या उनसे कोई गलतबयानी सामने आएगी, तो उससे आहत व्यक्ति या पक्ष के पास जवाब देने का अवसर तो मौजूद ही रहेगा। एक बार एक फिल्म पर प्रतिबंध से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि असहमत व्यक्ति फिल्म ना देखने या अभिव्यक्ति के अपने माध्यम से उसका जवाब देने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन लोकतंत्र में कलाकृति या वैचारिक अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन ये उस दौर की बात है, जब प्रतिबंध सरकार का विशेषाधिकार समझा जाता था। तब परोक्ष दबाव या सामाजिक ट्रोलिंग के जरिए अघोषित प्रतिबंध का चलन नहीं था। ताजा मामले में प्रत्यक्ष रूप से सरकार कहीं मौजूद नहीं है। मगर देश के मौजूदा सियासी माहौल का गहरा साया इस पर साफ देखा जा सकता है। सोनिया गांधी की आत्म-कथा- 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' को जो प्रकाशक अमेरिका में छाप रहा है, खबरों के मुताबिक उससे ही जुड़े भारतीय प्रकाशक ने भारत में इसे जारी करने से इनकार कर दिया है। बताया जाता है कि भारतीय संस्करण में सोनिया गांधी से कुछ हिस्सों को हटाने को कहा गया, जिससे उन्होंने मना कर दिया। गुजरे सवा दशक में उसी प्रकाशक ने भारत में कई किताबों को इसीलिए नहीं प्रकाशित किया, क्योंकि उससे सत्ता या अन्य शक्तिशाली पक्षों के नाराज होने का अंदेशा था। जबकि कुछ लेखकों ने प्रकाशकों के दबाव में आपत्तिजनक हिस्से हटा कर किताब छपवा लेना बेहतर समझा। ऐसा करने से सोनिया गांधी का इनकार काबिल-ए-तारीफ निर्णय है। मगर इस घटनाक्रम ने भारत में अभिव्यक्ति के सिकुड़ते दायरे को जग-जाहिर कर दिया है, जिससे लोकतंत्र की स्थिति पर उठे सवाल और संगीन हो गए हैं।

अमेरिका-चीन की एआई जंग के बीच भारत के सामने क्या है रास्ता?

कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई को लेकर अमेरिका और चीन के बीच वैश्विक प्रतिस्पर्धा लगातार तेज होती जा रही है। यह मुकाबला अब केवल बेहतर एआई मॉडल बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि चिप, अर्धचालक, कंप्यूटिंग क्षमता, आंकड़ा केंद्र, निवेश, शोध, प्रतिभा, विनिर्माण और वैश्विक बाजार तक फैल चुका है। ऐसे समय में सबसे बड़ा सवाल भारत के सामने है कि वह इस बदलती तकनीकी दुनिया में किस दिशा में आगे बढ़े और अमेरिका तथा चीन की प्रतिस्पर्धा के बीच अपनी रणनीतिक स्थिति कैसे मजबूत करे। ब्रिक्स बैठक के बाद एआई को लेकर अमेरिका और चीन की प्रतिस्पर्धा ने एक नया आयाम हासिल किया है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ब्रिक्स देशों के लिए खुला स्रोत एआई समुदाय बनाने में चीन की अग्रणी भूमिका की घोषणा की है। इसके तहत बड़े भाषा मॉडल के विकास और उपयोग में सहयोग, विशेष प्रशिक्षण तथा खुले एआई पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने की बात कही गई है। इसके जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एआई की दौड़ में अमेरिका के आगे होने का दावा किया है। ऐसे में यह समझना महत्वपूर्ण है कि वास्तव में अमेरिका और चीन के बीच कितना अंतर है और आने वाले वर्षों में यह प्रतिस्पर्धा किस दिशा में जा सकती है।

एआई के क्षेत्र में अमेरिका अभी भी कई महत्वपूर्ण मोर्चों पर चीन से आगे है। अमेरिका के पास अत्याधुनिक एआई मॉडल, उन्नत एआई चिप, विशाल कंप्यूटिंग क्षमता, हाइपरस्केल आंकड़ा केंद्र, क्लाउड सेवाएं, विश्वविद्यालयों और निजी कंपनियों का मजबूत शोध तंत्र तथा बड़े पैमाने पर उद्यम पूंजी उपलब्ध है। एनवीडिया जैसी कंपनियों की एआई चिप तकनीक ने अमेरिका को इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण रणनीतिक बढ़त दी है।

दूसरी ओर, चीन की सबसे बड़ी ताकत उसका विशाल घरेलू बाजार, बड़े पैमाने पर विनिर्माण, राज्य समर्थित निवेश और एआई को उद्योगों के साथ जोड़ने की क्षमता है। चीन मोबाइल तकनीक, विद्युत वाहन, रोबोटिक्स, विनिर्माण, निगरानी व्यवस्था, वस्तु प्रबंधन और सरकारी सेवाओं जैसे क्षेत्रों में एआई के उपयोग को तेजी से बढ़ा रहा है। खुला स्रोत और कम लागत वाले एआई मॉडल के क्षेत्र में भी चीन ने मजबूत चुनौती पेश की है।

अमेरिका के नेतृत्व वाले 'पैक्स सिलिका संगठन' में 34 देश शामिल हैं, जिनमें भारत भी एक सदस्य है। वहीं चीन के नेतृत्व वाले 'वर्ल्ड एआई कोआपरेशन ऑर्गेनाइजेशन' में 29 देश शामिल हैं। चीन की ओर से ब्रिक्स देशों के लिए खुला स्रोत एआई समुदाय बनाने का प्रस्ताव इस प्रतिस्पर्धा को और महत्वपूर्ण बना देता है।

अमेरिका ने अत्यधिक उन्नत चिप, अर्धचालक उपकरण, क्लाउड पहुंच और कुछ अत्याधुनिक एआई मॉडल से संबंधित निर्यात नियंत्रण लागू किए हैं। इन तकनीकों को भरोसेमंद साझेदारों के साथ साझा करने की नीति ने दुनिया के कई देशों के सामने तकनीकी विकल्पों को लेकर नई चुनौती पैदा की है। दूसरी ओर, चीन ने दुर्लभ मृदा खनिजों के निर्यात पर नियंत्रण के माध्यम से यह संकेत दिया है कि तकनीकी आपूर्ति श्रृंखला में उसकी भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना कि 'जो एआई जीतेगा, वही जीतेगा' इस प्रतिस्पर्धा की रणनीतिक गंभीरता को दर्शाता है। एआई अब केवल तकनीकी विकास का विषय नहीं रह गया है, बल्कि यह आर्थिक शक्ति, राष्ट्रीय सुरक्षा, उद्योग, व्यापार और वैश्विक प्रभाव से सीधे जुड़ चुका है। तकनीकी स्थिति को आठ प्रमुख क्षेत्रों में देखा जाए तो पांच क्षेत्रों में अमेरिका को बढ़त हासिल है, जबकि तीन क्षेत्रों में चीन मजबूत स्थिति में है। पहला, अत्याधुनिक एआई मॉडल के क्षेत्र में अमेरिका आगे है। समग्र प्रदर्शन के मामले में अमेरिकी मॉडल अभी बढ़त बनाए हुए हैं। दूसरा, एआई चिप और ग्राफिक्स प्रसंस्करण इकाई के क्षेत्र में भी अमेरिका को महत्वपूर्ण लाभ है। एनवीडिया की तकनीकी और बाजार स्थिति इसका बड़ा कारण है।

तीसरा, एआई कंप्यूटिंग और आंकड़ा केंद्र के क्षेत्र में अमेरिका आगे है। विशाल निवेश, उन्नत चिप और बड़े पैमाने के बुनियादी ढांचे ने उसे मजबूत स्थिति दी है। चौथा, एआई शोध पारिस्थितिकी तंत्र में अमेरिका की बढ़त है। विश्वविद्यालयों, बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों और उद्यम पूंजी का संयोजन अमेरिका को मजबूत आधार देता है। पांचवां, वैश्विक एआई पारिस्थितिकी तंत्र में भी अमेरिका आगे है। सहयोगी देशों, कंपनियों और क्लाउड सेवाओं का व्यापक नेटवर्क उसे लाभ देता है। छठा, अर्धचालक विनिर्माण के कुछ क्षेत्रों में चीन की स्थिति मजबूत है। बड़े पैमाने का उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला उसकी बड़ी ताकत है। सातवां, खुले स्रोत और कम लागत वाले एआई मॉडल के क्षेत्र में चीन तेजी से चुनौती पेश कर रहा है। डीपसीक जैसे मॉडल ने लागत आधारित प्रतिस्पर्धा को नया रूप दिया है। आठवां, एआई की स्थापना और औद्योगिक उपयोग के क्षेत्र में चीन की बड़ी ताकत है। विशाल विनिर्माण क्षमता और घरेलू बाजार के कारण चीन एआई को वास्तविक अर्थव्यवस्था से तेजी से जोड़ रहा है।

इस तरह इन आठ क्षेत्रों में पांच में अमेरिका और तीन में चीन को बढ़त हासिल है। ब्रुकिंग्स के अप्रैल 2026 के आकलन के अनुसार, चीन के शीर्ष एआई मॉडल अभी अमेरिकी अत्याधुनिक मॉडल से कुछ महीने या उससे अधिक पीछे हैं। अमेरिकी मॉडल तार्किक क्षमता, गणित, कूटलेखन तथा लंबे समय तक चलने वाले स्वायत्त कार्यों और एजेंट आधारित कार्यों में समग्र बढ़त रखते हैं।

हालांकि अमेरिका तकनीकी रूप से आगे है, लेकिन चीन को कम आंकना बड़ी गलती होगी। चीन की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह एआई को पूरे औद्योगिक तंत्र से जोड़ने में तेजी दिखा रहा है। विद्युत वाहनों से लेकर रोबोटिक्स और विनिर्माण तक एआई का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद चीन ने अपने एआई चिप पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने की कोशिश तेज कर दी है। हालांकि अभी चीनी विकल्प अमेरिकी एनवीडिया के स्तर और पैमाने तक नहीं पहुंचे हैं। उच्च बैंडविड्थ मेमोरी जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों की उपलब्धता भी चीन के सामने एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। एक महत्वपूर्ण संकेत यह भी है कि अमेरिका और चीन मिलकर वैश्विक कंप्यूटिंग, निवेश और एआई मॉडल के लगभग 90 प्रतिशत हिस्से पर नियंत्रण रखते हैं। इसका अर्थ है कि दुनिया के बाकी देशों के लिए अपनी स्वतंत्र एआई क्षमता विकसित करना आसान नहीं होगा।

अमेरिका की असली ताकत केवल उसके एआई मॉडल नहीं हैं। उसके पास एक ऐसा संपूर्ण एआई तकनीकी ढांचा है, जिसे चीन के लिए पूरी तरह दोहराना कठिन है। इसमें एनवीडिया की एआई चिप, अर्धचालक डिजाइन, क्लाउड सेवाएं, बड़े आंकड़ा केंद्र, ओपनएआई, एंथ्रोपिक और गूगल जैसी कंपनियां, उद्यम पूंजी तथा वैश्विक स्तर पर काम करने वाला विकासकर्ता समुदाय शामिल हैं। यही कारण है कि अमेरिका केवल बेहतर एआई मॉडल तैयार नहीं कर रहा, बल्कि एआई की वैश्विक आधारभूत अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव बनाए हुए है। हालांकि यह बढ़त स्थायी मानी जाए, ऐसा भी नहीं है। अगले तीन से पांच वर्षों में अमेरिका और चीन के बीच मुकाबला बेहद करीबी हो सकता है। दीर्घकाल में चीन की विशाल विनिर्माण क्षमता, घरेलू बाजार और राज्य समर्थित निवेश अमेरिका की मौजूदा बढ़त को चुनौती दे सकते हैं।

डिजिटल युग और एआई में हिंदी: चुनौती या नया अवसर

21वीं सदी सूचना प्रौद्योगिकी और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (एआई) की सदी है। एक दौर था जब तकनीक और इंटरनेट की दुनिया में अंग्रेजी का एकछत्र राज माना जाता था और यह आशंका जताई जाती थी कि डिजिटल क्रांति भारतीय भाषाओं, विशेषकर हिंदी को हाशिए पर धकेल देगी। परंतु आज परिदृश्य इसके ठीक उलट है। डिजिटल युग और एआई के इस दौर में हिंदी न केवल अपनी उपस्थिति मजबूती से दर्ज करा रही है, बल्कि विकास के नए आयाम भी तलाश रही है। ऐसे में यह सवाल बेहद प्रासंगिक हो जाता है कि क्या यह दौर हिंदी के अस्तित्व के सामने कोई संकट खड़ा कर रहा है या फिर यह उसकी प्रगति का एक ऐतिहासिक अवसर है?

नि:संदेह, तकनीक के शुरुआती दौर में हिंदी के सामने चुनौतियाँ कम नहीं थीं। इंटरनेट की बुनियाद और कोडिंग मुख्य रूप से रोमन लिपि पर केंद्रित थी। देवनागरी लिपि के लिए मानक फॉन्ट और सहज कीबोर्ड का न होना एक बड़ी तकनीकी बाधा थी। इसके अलावा, एआई आधारित मॉडलों को प्रशिक्षित करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले डिजिटल डेटासेट की आवश्यकता होती है। इंटरनेट पर मानक और शुद्ध हिंदी सामग्री की सीमित उपलब्धता के कारण शुरुआती वॉयस असिस्टेंट और अनुवाद टूल्स कई बार भाषा के व्याकरण और संदर्भ को सही ढंग से नहीं पकड़ पाते थे।

हालाँकि, जैसे-जैसे तकनीक का प्रसार भारत के छोटे शहरों और ग्रामीण अंचलों तक हुआ, डिजिटल परिदृश्य पूरी तरह बदल गया। टेक कंपनियों को यह समझने में देर नहीं लगी कि भारत का असली और विशाल बाज़ार गैर-अंग्रेजी भाषी आबादी में बसता है। आज गूगल, यूट्यूब और विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर सबसे अधिक खोज और कंटेंट की खपत हिंदी में हो रही है।

एआई और वॉयस टेक्नोलॉजी ने तो साक्षरता और भाषा के बीच की दूरी को ही मिटा दिया है। गूगल असिस्टेंट या एलेक्सा जैसे टूल्स की मदद से जो लोग लिखना या टाइप करना नहीं जानते, वे भी केवल अपनी आवाज़ के बल पर जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इसने हिंदी भाषी आम जनमानस के लिए सूचना और ज्ञान का अधिकार वास्तव में सुलभ बना दिया है।

इसी प्रकार, एआई आधारित न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन ने दुनिया भर के ज्ञान-विज्ञान, चिकित्सा, विधि और प्रशासनिक साहित्य को हिंदी में अनूदित करने की प्रक्रिया को गति दी है। आज डिजिटल युग ने हिंदी कंटेंट क्रिएटर्स, पत्रकारों, ब्लॉगर्स और पॉडकास्टर्स के लिए संभावनाओं के असीम द्वार खोल दिए हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और मीडिया हाउसों में हिंदी की बढ़ती माँग ने युवाओं के लिए रोज़गार के नए और आकर्षक अवसर पैदा किए हैं। तथापि, इस उजले पक्ष के साथ एक सावधान करने वाला पहलू भी है। एआई और मशीन जनित सामग्री के अति-प्रयोग से भाषा की शुद्धता, उसकी मौलिक आत्मा और व्याकरणिक सौंदर्य के क्षरण की संभावना बनी रहती है। हिंग्लिश का बढ़ता प्रभाव और मशीनी अनुवाद का अंधाधुंध उपयोग भाषा के लालित्य को चोट पहुँचा सकता है। अत: आवश्यकता इस बात की है कि हिंदी के विद्वान, भाषाविद और तकनीकी विशेषज्ञ मिलकर काम करें। हमें एआई मॉडलों को समृद्ध, प्रामाणिक और उच्च स्तरीय हिंदी डेटासेट से प्रशिक्षित करना होगा। निष्कर्षत:, एआई और डिजिटल क्रांति हिंदी के लिए कोई खतरा नहीं, बल्कि एक स्वर्णिम अवसर है। तकनीक ने हिंदी को महज़ साहित्यिक गोष्ठियों और आधिकारिक औपचारिकताओं से निकालकर वैश्विक डिजिटल पटल पर स्थापित कर दिया है। यदि हम भाषा की मौलिकता की रक्षा करते हुए इस तकनीक को पूरी क्षमता से अपनाएँ, तो आने वाले समय में हिंदी विश्व की सबसे सशक्त और ज्ञान-समृद्ध डिजिटल भाषाओं में अग्रगण्य होगी ।

मध्यप्रदेश हिन्दी में एमबीबीएस की पढ़ाई प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य

स्टीफन स्पेंडर की तरह कहें तो सर्जना के स्तर पर भाषा, अपनी भाषा एक आध्यात्मिक गतिविधि है या टाल्सटाय के शब्दों में यहाँ आध्यात्मिक सक्रियता के स्त्रोत प्रवाहित होते हैं या मुक्तिबोध के शब्दों में 'स्व' से ऊपर उठना, अन्य के मर्म में प्रवेश करना मनुष्यता का सबसे बड़ा लक्षण है। और यह लक्षण हिन्दी में शब्द बनते ही दिखाई देने लगता है। आकार, अक्षर और ध्वनि का एकाकार जिस भाषा में हुआ वह सिर्फ हिन्दी है।

इसलिए मैं गिलक्राइस्ट जैसे लोगों का सख्त विरोधी हूं जो हिन्दी को गंवारू और हिन्दुओं की भाषा कहता था। 'गार्सा-द-तासी' ने लिखा था हिन्दी में हिन्दू धर्म का आभास है। इसलिए यदि हिन्दी के लोकवृत्त को समझना हो तो भक्ति आंदोलन को समझना जरुरी है। जब कबीर कहते हैं 'कबीरा खड़ा बाज़ार में, लिए लुकाठी हाथ' तो वो बाजार का नहीं उसकी माया का विरोध कर रहे हैं या विद्यापति की उम्मीद 'बिपत अपत तरु पाओल रे पुन नव नव पात'। यह हिन्दी का संदेश है कि जो पत्ते सूख गए हैं तो उनमें फिर नए पत्ते आएंगे। हमारे देश में उदारवाद के पगचिन्ह भक्तिकाल में साफ-साफ दिखाई देते हैं। आखिर मथुरा में आचार्य वल्लभ पहुंचे, चैतन्य पहुंचे और इन सभी ने सामुदायिक खाइयों को पाटने का काम किया।

हिन्दी की पाचनशक्ति अद्भुत है। इसमें दुनियाभर की भाषाओं के शब्द हैं और वे अतिथि शब्द नहीं है बल्कि आत्मसात कर लिए गए शब्द हैं। ऐसा दुनिया की कोई भाषा नहीं कर सकी। अंग्रेजी भी नहीं जिसकी सर्वाधिक दुग्गी हमारे देश में पीटी जाती है। अंग्रेजी से पहले वहाँ लैटिन और ग्रीक बोली जाती थी यही अभिजात्य वर्ग की भाषा थी। अंग्रेजी उस समय अभिजात्यों की नहीं हाशिए पर जी रहे गरीबों और मजदूरों की भाषा थी। उनके शब्द लिए गए मगर अंग्रेजी उन्हें आत्मसात नहीं कर पायी। जैसे जॉन कीट्स की एक कविता का शीर्षक है ला बेले डेम सैंस मर्सी यानि एक दयाहीन सुंदर महिला यह शीर्षक 15वीं शताब्दी का है। अंग्रेजी में यह कविता बेहद चर्चित है, जिसमें एक परी शूरवीर को सम्मोहित करके अप्रिय भाग्य का श्राप देती है। हिंदी सिर्फ एक भाषा ही नहीं भारत की संस्कृति है। यह उदार और निर्माणात्मक में सुन भर लीजिए तो हिन्दी स्मृति में बसने लगती है। हमारे यशस्वी और श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पंक्तियां है- आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प लें, अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर, हर मुश्किल को पार कर,घोर अंधेरे को मिटाने, अभी तो सूरज उगा है। आज सूरदास कोलंबिया में, मीरा अमेरिका के कई बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही हैं। जायसी पढ़ाए जा रहे हैं। हिन्दी का अर्थ ही नहीं शब्द-शब्द श्लोक है। जो बोलते ही सूखे गेहूँ के दाने सा खनकता है। हिन्दी के निकट बैठकर महात्मा गांधी दिखाई देने लगते हैं अर्थात हर गरीब मन का दर्द जहां नव गीत में ढ़लने लगे वह हमारी भाषा है हिंदी।

देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निरंतर प्रयास रहा है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था भारतीय भाषाओं, भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय प्रतिभा की शक्ति के अनुरूप आगे बढ़े। लंबे समय तक अंग्रेजी को उच्च शिक्षा और विशेषकर चिकित्सा एवं तकनीकी शिक्षा का प्रमुख माध्यम माना जाता रहा। इसका परिणाम यह हुआ कि ग्रामीण, गरीब, किसान और सामान्य परिवारों से आने वाले अनेक प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए उच्च स्तरीय शिक्षा तक पहुंच का मार्ग अपेक्षाकृत कठिन बना रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 ने शिक्षा में भारतीय भाषाओं के महत्व को नई दिशा दी। यह केवल भाषा परिवर्तन का विषय नहीं है बल्कि यह शिक्षा को अधिक समावेशी, सहज और विद्यार्थी-केंद्रित बनाने की व्यापक सोच का हिस्सा बना।

प्रधानमंत्री जी के इसी संकल्प को धरातल पर उतारते हुए मध्यप्रदेश ने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल की। मुझे इस बात का गर्व है कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य करते हुए हम मध्यप्रदेश का नाम उस ऐतिहासिक उपलब्धि से जोड़ने में सफल रहे, जब मध्यप्रदेश ने हिन्दी माध्यम में एमबीबीएस की पढ़ाई प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य होने का गौरव हासिल किया। यह केवल मध्यप्रदेश के लिए उपलब्धि नहीं थी बल्कि भारतीय भाषाओं के प्रति विश्वास को मजबूत करने वाला एक महत्वपूर्ण कदम था।

16 अक्टूबर 2022 वो ऐतिहासिक दिन जब भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के करकमलों द्वारा एमबीबीएस प्रथम वर्ष की हिन्दी पुस्तकों का विमोचन किया गया और हिंदी में मेडिकल शिक्षा के नए अध्याय का शुभारंभ हुआ। यह क्षण इसलिए भी ऐतिहासिक था क्योंकि पहली बार चिकित्सा जैसे अत्यंत तकनीकी और विशेषज्ञता वाले विषय में भारतीय भाषा को शिक्षा के प्रभावी माध्यम के रूप में बड़े स्तर पर स्थापित करने का प्रयास किया गया।

हमारा उद्देश्य कभी यह नहीं रहा कि हिन्दी को अंग्रेजी के विरोध में खड़ा किया जाए। उद्देश्य यह है कि भाषा किसी विद्यार्थी की प्रतिभा के मार्ग में बाधा न बने। रोजमर्रा की जिंदगी में जिस भाषा में विद्यार्थी सोचता है, परिवार से संवाद करता है और अपने अनुभवों को समझता है, उसी भाषा में कठिन अवधारणाओं को समझना उसके लिए स्वाभाविक रूप से अधिक सहज हो सकता है।

हिन्दी में एमबीबीएस का पाठ्यक्रम तैयार करना सामान्य अनुवाद का कार्य नहीं था। चिकित्सा विज्ञान की शब्दावली, अवधारणाओं और तकनीकी विषयों को विद्यार्थियों के लिए वैज्ञानिक रूप से सही, सहज और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना एक बड़ी चुनौती थी। इसी उद्देश्य से चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत हिन्दी में एमबीबीएस पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए पृथक हिन्दी पाठ्यक्रम प्रकोष्ठ का गठन किया गया तथा विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के माध्यम से कार्ययोजना तैयार की गई। चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञों की सहभागिता से पाठ्यक्रम और पुस्तकों को चरणबद्ध एवं व्यवस्थित रूप से तैयार करने का कार्य किया गया। हिन्दी पुस्तकों के रूपांतरण और चिकित्सा शिक्षा की इस पूरी प्रक्रिया को संस्थागत स्वरूप देने के लिए हिन्दी चिकित्सा प्रकोष्ठ 'मंदार' का विधिवत गठन किया गया। जिस प्रकार समुद्र मंथन से अमृत प्राप्त हुआ था, उसी प्रकार ज्ञान के मंथन, विशेषज्ञों के परिश्रम और संकल्प की साधना से 'मंदार' के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक नया अमृत निकला।

पर्वतारोहण से विदेशी मुद्रा जुटाने की होड़ में नेपाल के सामने बढ़ता पर्यावरणीय संकट

पर्वतारोहण रोमांच, साहस और जोखिम से भरा ऐसा शौक है, जिसमें मनुष्य प्रकृति की विराट शक्ति को चुनौती देते हुए दुर्गम चोटियों तक पहुंचने का प्रयास करता है। बर्फीली हवाओं, अत्यधिक ठंड, कम ऑक्सीजन, खतरनाक ढलानों और अचानक बदलते मौसम के बीच किसी पर्वत शिखर तक पहुंचना केवल शारीरिक क्षमता का प्रमाण नहीं, बल्कि संकल्प, धैर्य और जीवट का भी परिचायक है। पर्वतारोहण इसी कारण मनुष्य के साहस और उसकी सीमाओं को परखने वाली गतिविधि माना जाता है।

तेनजिंग नोर्के और एडमंड हिलेरी जैसे पर्वतारोहियों को अमर पहचान भी इसी साहसिक अभियान ने दिलाई। एवरेस्ट यानी सागरमाथा पर पहली सफल चढ़ाई ने पर्वतारोहण के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा और दुनिया भर के पर्वतारोहियों के लिए हिमालय को आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र बना दिया। आज भी एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचना दुनिया के हजारों पर्वतारोहियों के लिए जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता है।

विश्व के दस सर्वोच्च पर्वत शिखरों में से आठ भारत के पड़ोसी देश नेपाल और हिमालयी क्षेत्र में स्थित हैं। इनमें सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8849 मीटर से अधिक है। नेपाल में इसे सागरमाथा कहा जाता है। हिमालय की इन ऊंची चोटियों तक पहुंचने में स्थानीय शेरपाओं की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों, ऊंचाई और मौसम की चुनौतियों के बीच उनकी विशेषज्ञता और अनुभव की दुनिया भर में प्रशंसा की जाती है। लेकिन पर्वतारोहण का यह गौरवपूर्ण और रोमांचक पक्ष अब एक गंभीर सवाल से घिरता जा रहा है। सवाल यह है कि क्या हिमालय की चोटियों को पर्यटन और विदेशी मुद्रा अर्जित करने के साधन के रूप में इस्तेमाल करते-करते नेपाल उनकी प्राकृतिक क्षमता पर जरूरत से ज्यादा दबाव तो नहीं डाल रहा? पर्वतारोहण से कमाई बढ़ाने की कोशिश और हिमालय के पर्यावरण को सुरक्षित रखने की आवश्यकता के बीच संतुलन का सवाल अब पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।

नेपाल के लिए पर्वतारोहण केवल रोमांच और पर्यटन का विषय नहीं है। यह विदेशी मुद्रा अर्जित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है। पिछले वर्ष पर्वतारोहण के जरिये नेपाल को 5.9 मिलियन डॉलर की कमाई हुई थी। इसमें तीन-चौथाई से अधिक योगदान माउंट एवरेस्ट का था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नेपाल की पर्यटन अर्थव्यवस्था में एवरेस्ट का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। गत वर्ष 12 अगस्त को सामने आई खबर के अनुसार नेपाल ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्वतारोहण का सहारा लेने की नई नीति पर काम किया। इस नीति के तहत अगले दो वर्षों के लिए दूरदराज के इलाकों में हिमालय की 97 चोटियों पर चढ़ाई को मुफ्त करने की बात कही गई थी। इसका उद्देश्य जाहिर तौर पर उन क्षेत्रों में पर्यटन और पर्वतारोहण गतिविधियों को बढ़ावा देना था, जहां पर्यटकों की आवाजाही अपेक्षाकृत कम है।

लेकिन इसी नीति के दूसरे पहलू ने सवाल खड़े किए। उसी वर्ष सितंबर से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर मुख्य पर्वतारोहण मौसम में चढ़ाई के लिए परमिट शुल्क बढ़ाकर 15,000 डॉलर कर दिया गया। यानी एक ओर नेपाल दूरदराज की चोटियों पर पर्वतारोहण को प्रोत्साहित करने के लिए शुल्क हटाने की बात कर रहा था, वहीं दूसरी ओर एवरेस्ट जैसी अत्यधिक लोकप्रिय चोटी से अधिक राजस्व अर्जित करने के लिए परमिट शुल्क बढ़ाया गया।

एवरेस्ट की लोकप्रियता लगातार बढ़ी है। वर्ष 2024 में एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए 400 से भी अधिक परमिट जारी किए गए थे। बड़ी संख्या में पर्वतारोहियों के पहुंचने का सीधा असर दुनिया की इस सर्वोच्च चोटी के पर्यावरण और पर्वतीय पारिस्थितिकी पर पड़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि 8849 मीटर से अधिक ऊंची एवरेस्ट चोटी हाल के वर्षों में भीड़भाड़, पर्यावरण संबंधी चिंताओं और चढ़ाई के दौरान होने वाले जानलेवा हादसों से जूझ रही है। पर्वतारोहण के अनुकूल मौसम सीमित होने के कारण बड़ी संख्या में पर्वतारोही एक ही अवधि में चोटी पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। इससे कई बार रास्तों पर लंबी कतारें लगती हैं और पर्वतारोहियों के लिए जोखिम भी बढ़ जाता है।

यह स्थिति केवल चढ़ाई की कठिनाई का प्रश्न नहीं है। अधिक संख्या में पर्वतारोहियों का अर्थ है अधिक शिविर, अधिक उपकरण, अधिक ऑक्सीजन सिलेंडर, अधिक पैकेजिंग सामग्री और अधिक मानव अपशिष्ट। इतनी ऊंचाई पर छोड़े गए कचरे को वापस नीचे लाना आसान काम नहीं है। अत्यधिक ठंड, कम ऑक्सीजन और दुर्गम रास्तों के कारण सफाई अभियान स्वयं एक जोखिम भरा अभियान बन जाता है। एवरेस्ट पर बढ़ते दबाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अप्रैल 2024 में नेपाल की सर्वोच्च अदालत ने नेपाल सरकार को एवरेस्ट और अन्य कई पर्वत चोटियों के लिए जारी किए जाने वाले परमिट की संख्या सीमित करने का आदेश दिया था। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा था कि पहाड़ों की क्षमता का सम्मान किया जाना चाहिए।

यह आदेश पर्वतीय पर्यावरण को लेकर बढ़ती चिंता का महत्वपूर्ण संकेत था। इसका मूल संदेश यह था कि प्राकृतिक संसाधनों और पर्वतीय पारिस्थितिकी की अपनी एक सीमा होती है और पर्यटन या राजस्व बढ़ाने के नाम पर उस सीमा की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए।

एक कंटेस्टेंट के तौर पर नहीं जीत पाई थीं 'इंडियन आइडल' शो, आज तकरीबन हर बड़ी फिल्मों में होते हैं नेहा के गाने

नेहा कक्कड़ को भला आज कौन नहीं जानता. बहुत ही संघर्ष के बाद वो आज बॉलीवुड) में एक सफल प्लेबैक सिंगर के तौर पर जानी जाती हैं. लोग उन्हें सेल्फी क्वीन के नाम से बुलाते हैं. साल 2006 में हुए रियलिटी शो 'इंडियन आइडल 2' में बतौर कंटेस्टेंट नेहा कक्कड़ ने हिस्सा लिया था. हालांकि इस शो में नेहा विनर नहीं रही थीं लेकिन उन्होंने अपने हौसले की उड़ान को अपने अंदर जिंदा रखा और आज वो एक से बढ़कर एक गाने फिल्मों के लिए गा रही हैं. नेहा आज अपना जन्मदिन मना रही हैं. उनके जन्मदिन के मौके पर आज हम आपको उनसे जुड़ी कुछ अनसुनी बातों को बताएंगे.नेहा कक्कड़ का जन्म 6 जून 1988 को उत्तराखंड के ऋषिकेश में हुआ था. नेहा को लोग इंडियन शकीरा के नाम से भी पुकारते हैं. नेहा के पिता का नाम ऋषिकेश कक्कड़ है जो कि एक गैर-सरकारी संस्था में काम करते हैं और उनकी मां का नाम नीति कक्कड़ है जो कि एक गृहिणी हैं. नेहा की एक बड़ी बहन हैं सोनू कक्कड़ जो कि खुद एक क्लासिकल सिंगर हैं और उनके भाई का नाम है टोनी कक्कड़ जो कि एक सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर हैं. नेहा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के हौली पब्लिक स्कूल से की थी. जब वो ग्यारहवीं की पढ़ाई कर रही थीं, उसी वक्त उन्होंने 'इंडियन आइडल 2' में बतौर प्रतिभागी नजर आई थीं. हालांकि, वो जब महज 4 साल की ही थीं, उसी वक्त से वो भजन गाया करती थीं। नेहा कक्कड़ का एक बॉयफ्रेंड था जिनका नाम हिमांश कोहली था. वो एक अबिनेता हैं. दोनों ने एक-दबसरे को काफी समय तक डेट किया लेकिन किसी वजह से दोनों का रिश्ता टूट गया जिसके बाद नेहा कक्कड़ ने साल 2020 में अपने कथित बॉयफ्रेंड रोहनप्रीत सिंह से 24 अक्टूबर को शादी कर ली थी. बता दें कि, रोहनप्रीत सिंह भी पेशे से एक गायक हैं. नेहा ने कलर्स के फेमस शो 'ना आना इस देश मेरी लाडो' का टाइटल सॉन्ग भी गा चुकी हैं. साल 2008 में नेहा ने मीत ब्रदर्स के जरिए कंपोज किए गए एल्बम 'नेहा द रॉक स्टार' से अपनी गायकी की शुरुआत की थी. नेहा ने अब तक कई सारे हिट गाने बॉलीवुड को दिए हैं. वो अब तक कई तरह के लाइव शो के साथ ही जगराता भी कर चुकी हैं. उन्होंने 1000 से भी ज्यादा लाइव शोज किए हैं. नेहा यूट्यूब पर भी काफी मशहूर हैं।

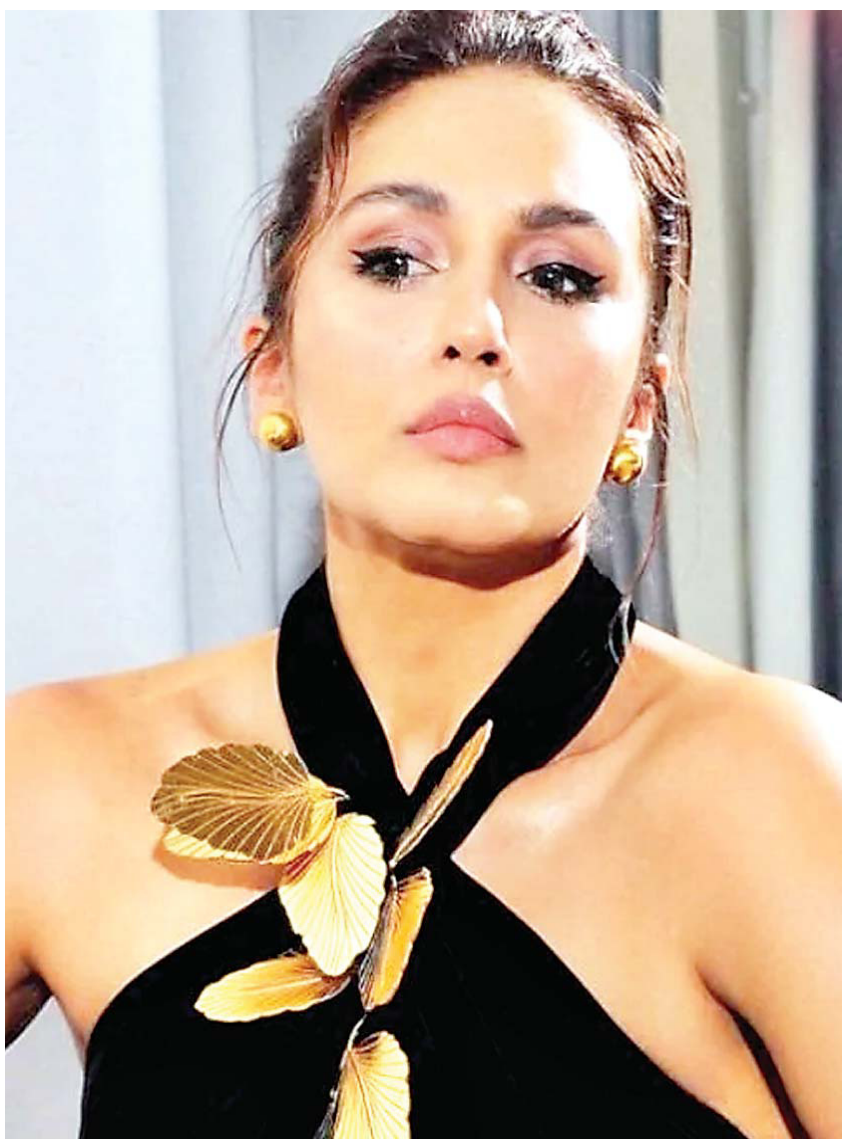

हुमा कुरैशी ने न्यूड सीन से किया साफ इनकार

अभिनेत्री हुमा कुरैशी इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'बेबी डू डाई डू' और यश की बहुचर्चित फिल्म 'टॉक्सिक' को लेकर सुर्खियों में हैं। हुमा की महिला-प्रधान एक्शन फिल्म 'बेबी डू डाई डू' हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। बॉक्स ऑफिस पर इसका मुकाबला आलिया भट्ट और शरवरी स्टारर 'ऐल्फा' से हो रहा है।हालांकि, हुमा इस फिल्म को प्रतिस्पर्धा के तौर पर नहीं देखतीं। उनका कहना है कि यह महिला-केंद्रित एक्शन फिल्मों के लिए एक सकारात्मक दौर है और दर्शकों के पास अब मजबूत महिला किरदारों वाली कई फिल्में देखने का विकल्प मौजूद है।

वहीं, हुमा साउथ सुपरस्टार यश की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'टॉक्सिक' का भी हिस्सा हैं। फिल्म के टीजर और यश के कुछ सीन को लेकर सोशल मीडिया पर उठ रहे विवाद पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है।हुमा ने कहा कि किसी भी फिल्म को रिलीज से पहले जज करना सही नहीं है। उन्होंने दर्शकों से अपील की कि पहले पूरी फिल्म देखें, उसके बाद ही अपनी राय बनाएं। उनके मुताबिक, किसी फिल्म या उसके कलाकारों के बारे में अधूरी जानकारी के आधार पर निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है।हुमा कुरैशी ने अपने हालिया बयान से एक बार फिर चर्चा बटोर ली है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वह अपने करियर में कभी भी न्यूड सीन नहीं करेंगी। हुमा ने इस फैसले के पीछे अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों और मूल्यों का जिक्र करते हुए कहा कि, मेरे भी पिता हैं, भाई हैं और एक परिवार है। मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहूंगी जिससे उन्हें शर्मिंदा होना पड़े।हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वह किसी अन्य कलाकार के फैसले को जज नहीं कर रही हैं। हुमा ने कहा, कई लोग न्यूड सीन करते हैं और वो उसमें सहज होते हैं, मैं उनके फैसले का सम्मान करती हूं। उनके इस बयान की सोशल मीडिया पर सराहना हो रही है।

परिवार से लड़कर मुंबई भागकर आई थीं तृप्ति डिमरी

मुश्किल घड़ी में सिर्फ बहन ने ली सुध

तृप्ति डिमरी को मूवीज में काम करते हुए 10 साल से अधिक समय हो चुका है। एक्ट्रेस ने बताया कि जब वह मुंबई आईं तो उन्हें परिवार में सिर्फ एक इंसान का सपोर .

एंटरटेनमेंट डेस्क, मुंबई ब्यूरो। इंटरनेट मीडिया के वर्तमान दौर में ट्रोलिंग और तमाम नकारात्मक टिप्पणियों के बीच अपने समर्थन या प्रशंसा में लिखी एक बात भी कलाकारों को बहुत सुकून देती है। एनिमल और कला फिल्मों की अभिनेत्री तृप्ति डिमरी के लिए ऐसी परिस्थितियों में किसी से सपोर्ट मिलना बहुत खुशी की बात होती है।

तृप्ति सोशल मीडिया पर होने वाली ट्रोलिंग को लेकर कहती हैं, मैं पिछले दस वर्ष से अभिनय कर रही हूं। मुंबई आने के बाद से मेरी जिंदगी में बहुत उतार-चढ़ाव आए, लेकिन उनके बारे में कोई बात नहीं करता है। बस किसी एक नकारात्मक बात को पकड़ लेते हैं और वही बार-बार दिखाते हैं। मेरे कुछ सपने हैं। मैं आज यहां बहुत मेहनत से पहुंची हूं।

एक्ट्रेस ने दिल का हाल बयां करते हुए आगे कहा,अपने परिवार से लड़ी हूं और घर से भागकर मुंबई आई हूं। इसके लिए मैं अपने भाग्य को भी धन्यवाद कहूंगी कि मेरे इस सफर में कुछ शानदार लोग और सह कलाकार भी मिले। ऐसे में जब कोई सिर्फ नकारात्मक बातें लिखता है तो उससे मुझे भी तकलीफ होती है।इस बीच अगर किसी का सपोर्ट मिलता है तो बहुत खुशी मिलती है। लगता है कि हां, किसी ने तो मेरे सफर को करीब से देखा है।

आगे तृप्ति अपने जीवन में अपनी बहन से मिले सपोर्ट को लेकर कहती हैं कि, मेरी जिंदगी में कई ऐसे भी मौके रहे, जब किसी ने मेरा सपोर्ट नहीं किया, लेकिन मेरी बहन हमेशा मेरे साथ खड़ी रही। उस समय उनकी अपनी जिंदगी में भी अलग लड़ाईयां चल रही थीं। फिर भी वह मुझे हर दिन फोन करती थीं कि मैंने खाना खाया या नहीं। ऑडिशन सही गया या नहीं। जब भी मुझे किसी काम के लिए पैसों की आवश्यकता होती तो वो ही मेरी मदद करती थीं। आज भी मेरा कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो वह सबसे पहले देखती हैं।

आपको बता दें कि तृप्ति डिमरी की फिल्म मां-बहन बीते दिनों ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, जिसे दर्शकों से शानदार रिस्पांस मिल रहा है। फिल्म में उनके साथ माधुरी दीक्षित और धारण मुख्य भूमिका में हैं।

सोनाक्षी सिन्हा को इन ब्लॉकबस्टर फिल्मों को ठुकराने का आज भी है पछतावा!

आज वो अपनी हर फिल्म के लिए करोड़ों में चार्ज करती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनसे भी कई बार कई बड़ी गलतियां हुई हैं, जिसको लेकर वो आज भी पछताती हैं. जी हां, सोना ने भी बॉलीवुड की कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों को लात मारी है, जिसके लिए उनको आज कहीं न कहीं इस बात का गम है कि उनसे ये गलती हुई है.

सोनाक्षी सिन्हा आज यानी 2 जून के दिन सोनाक्षी सिन्हा अपना 35वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरूआत इंडस्ट्री के सुपरस्टार सलमान खान के साथ फिल्म दंबग से की थी. सोनाक्षी की ये भले ही पहली फिल्म थी, लेकिन वो रातों-रात स्टार बन गईं. उनके अभिनय से लेकर उनकी खूबसूरती ने सभी का दिल जीत लिया था. इसके बाद वो सीरीज में नजर आ चुकी हैं. इसके अलावा भी सोना ने कई हिट और बड़ी फिल्मों में काम किया है.आज के समय में सोनाक्षी बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में अपनी पहचान बना चुकी हैं. आज वो अपनी हर फिल्म के लिए करोड़ों में चार्ज करती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनसे भी कई बार कई बड़ी गलतियां हुई हैं, जिसको लेकर वो आज भी पछताती हैं. जी हां, सोना ने भी बॉलीवुड की कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों को लात मारी है, जिसके लिए उनको आज कहीं न कहीं इस बात का गम है कि उनसे ये गलती हुई है. आज हम आपको उनकी इन्हीं फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं.हसीना पारकर : आप सभी को फिल्म हसीना पारकर तो याद ही होगी, जिसको मुंबई की एक दंबग गैंगस्टर लेडी पर बनाया गया है. इस फिल्म के लिए पहले सोनाक्षी सिन्हा को ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया.**मुबारकां** : डायरेक्टर अनीस बज्मी की कॉमेडी फिल्मों में से एक मुबारका इस फिल्म के लिए पहले सोनाक्षी सिन्हा को ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने इस फिल्म को किसी प्रोफेशनल रीजन के चलते मना कर दिया था.**हाउसफुल 4** : इसके अलावा सोना के पास अक्षय कुमार की कॉमेडी फिल्म हाउसफुल 4 का भी ऑफर मिला था, लेकिन खबरों की माने तो उन्होंने इसका हिस्सा बनने से भी इंकार कर दिया था.**रेस 2** : इसके अलावा उनको रेस 2 का भी ऑफर मिल चुका है. इसकी हर एक प्रैंचाइसी हिट रही है, लेकिन एक्ट्रेस ने इसके ऑफर को भी ठुमरा दिया था।, जिसके बाद फिल्म में इनरी जगह दूसरी एक्ट्रेस को मिल गई थी. फिल्म में सैफ अली खान, जॉन अब्राहम, दीपिका पादुकोण, अमीषा पटेल और अनिल कपूर प्रमुख भूमिका में थे। **उड़ता पंजाब** :पंजाब की कहानी को बयां करती शाहिद कपूर की हिट फिल्मों में से एक फिल्म उड़ता पंजाब को भी दर्शकों का बेहद प्यार मिला था।

राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में बक्सर की अनुष्का पाण्डेय ने जीता कांस्य पदक, ताइक्वांडो में राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया जिले का गौरव

मध्य प्रदेश के खांडवा में आयोजित 37वीं राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में 46-49 किलोग्राम भार वर्ग में अनुष्का ने हासिल किया कांस्य पदक, पढ़ाई के साथ खेल में भी लगातार कर रही शानदार प्रदर्शन

बक्सर (संवाददाता)। बक्सर जिले की होनहार बेटी अनुष्का पाण्डेय ने ताइक्वांडो के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। मध्य प्रदेश के खांडवा में 9 से 13 सितंबर 2026 तक आयोजित 37वीं राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में अनुष्का ने 46-49 किलोग्राम वजन समूह में कांस्य पदक हासिल कर बक्सर और बिहार का नाम रोशन किया। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया से सम्बद्ध विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश के विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच अनुष्का का कांस्य पदक हासिल करना उनके निरंतर अभ्यास, अनुशासन, मेहनत और खेल के प्रति समर्पण को दर्शाता है।

अनुष्का पाण्डेय का जन्म बक्सर में हुआ है और उनका जुड़ाव जिले से रहा है। वर्तमान में वह नई दिल्ली स्थित महाशय चुन्नी लाल सरस्वती बाल मंदिर, हरिनगर में कक्षा 11 की छात्रा हैं। पढ़ाई के साथ-साथ ताइक्वांडो में लगातार अभ्यास और प्रतियोगिताओं में भागीदारी के कारण उन्होंने कम उम्र में ही अपनी अलग पहचान बनाई है। शिक्षा और खेल दोनों क्षेत्रों के बीच संतुलन बनाते हुए अनुष्का ने विभिन्न स्तरों की प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का प्रभावशाली प्रदर्शन किया है।

अनुष्का की खेल यात्रा केवल एक प्रतियोगिता तक सीमित नहीं रही है। इससे पहले भी वह दिल्ली राज्य, दिल्ली क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक हासिल कर चुकी हैं। लगातार अलग-अलग स्तरों पर पदक जीतने का उनका सिलसिला उनकी खेल प्रतिभा और नियमित तैयारी को दर्शाता है। प्रतियोगिताओं में लगातार बेहतर प्रदर्शन करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी जगह बनाई है।

वर्ष 2025 में भी अनुष्का ने ताइक्वांडो प्रतियोगिता में उल्लेखनीय सफलता हासिल की थी। अंतरराष्ट्रीय ताइक्वांडो फेडरेशन द्वारा आयोजित 40वीं राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उन्होंने अपने प्रथम प्रयास में ही रजत पदक हासिल किया था। पहली ही कोशिश में राष्ट्रीय स्तर पर रजत पदक प्राप्त करना उनके लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। इसके बाद भी उन्होंने खेल के प्रति अपनी मेहनत और अभ्यास को जारी रखा और अब वर्ष 2026 में 37वीं राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल किया है।

मध्य प्रदेश के खांडवा में आयोजित 37वीं राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में अनुष्का ने 46-49 किलोग्राम वजन समूह में भाग लिया। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में विभिन्न क्षेत्रों से आए खिलाड़ियों के बीच मुकाबला हुआ। ऐसे प्रतिस्पर्धी माहौल में कांस्य पदक हासिल कर अनुष्का ने अपने खेल कौशल का प्रदर्शन किया। उनकी यह उपलब्धि उनके पिछले प्रदर्शन की निरंतरता के रूप में भी देखी जा रही है।

राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीतने के बाद बक्सर में उनके परिवार, परिचितों और खेल प्रेमियों में खुशी का माहौल है। अनुष्का की सफलता की जानकारी मिलने के बाद परिजनों और शुभचिंतकों ने प्रसन्नता व्यक्त की और उन्हें बधाई दी। परिवार के लोगों ने उनकी इस उपलब्धि को मेहनत, अनुशासन और लगातार अभ्यास का परिणाम बताया। अपनी सुपौत्री अनुष्का पाण्डेय की राष्ट्रीय स्तर की उपलब्धि पर प्रसिद्ध गीतकार एवं शिक्षाविद् श्रीभगवान पाण्डेय ने भी खुशी व्यक्त की। उन्होंने अनुष्का की सफलता पर प्रसन्नता जताई। वहीं अनुष्का के पिता इंजीनियर नीरज पाण्डेय सहित परिवार के अन्य सदस्यों ने भी उनकी उपलब्धि पर खुशी व्यक्त की। परिवार के लिए यह उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अनुष्का ने पढ़ाई के साथ खेल के क्षेत्र में भी लगातार अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाया है।

अनुष्का की उपलब्धि बक्सर जिले के उन युवाओं के लिए भी प्रेरणादायक है, जो खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में पदक हासिल करने के लिए केवल खेल प्रतिभा ही नहीं, बल्कि नियमित अभ्यास, अनुशासन, धैर्य और प्रतियोगिता के दबाव में बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता भी आवश्यक होती है। अनुष्का ने अलग-अलग स्तर की प्रतियोगिताओं में लगातार भाग लेकर और पदक हासिल कर अपनी खेल यात्रा को आगे बढ़ाया है।

ताइक्वांडो जैसे खेल में खिलाड़ी को शारीरिक क्षमता के साथ तकनीक, संतुलन, गति और अनुशासन पर भी विशेष ध्यान देना होता है। अनुष्का का लगातार प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन करना यह बताता है कि वह इस खेल को लेकर गंभीर हैं और अपनी प्रतिभा को प्रतियोगी स्तर पर लगातार निखार रही हैं। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कांस्य पदक उनकी इसी खेल यात्रा की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

बक्सर की बेटी के राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने की खबर से जिले के खेल प्रेमियों में भी उत्साह देखा जा रहा है। अनुष्का की सफलता ने यह संदेश दिया है कि उचित मेहनत और निरंतर अभ्यास के माध्यम से जिले की प्रतिभाएं भी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में अपनी पहचान बना सकती हैं। उनके प्रदर्शन से परिवार और बक्सर जिले से जुड़े लोगों में गर्व की भावना है।

अनुष्का की उपलब्धियों का सिलसिला दिल्ली राज्य और क्षेत्रीय प्रतियोगिताओं से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक जारी रहा है। स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक हासिल करने के बाद अब खांडवा की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कांस्य पदक उनके पदकों की सूची में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में जुड़ गया है। वर्ष 2025 में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में रजत पदक हासिल करने के बाद वर्ष 2026 में राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में कांस्य पदक प्राप्त करना उनके निरंतर प्रतियोगी अनुभव को दर्शाता है।

परिवार और शुभचिंतकों ने अनुष्का को उनकी उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए भविष्य में भी इसी तरह मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ने की कामना की है। राष्ट्रीय स्तर पर हासिल किया गया यह पदक उनके लिए आगे की प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अनुष्का फिलहाल कक्षा 11 की छात्रा हैं और शिक्षा के साथ खेल में अपनी सक्रियता बनाए हुए हैं।

बक्सर जिले की इस प्रतिभाशाली खिलाड़ी की उपलब्धि से स्थानीय स्तर पर खेल प्रतिभाओं को लेकर उत्साह बढ़ा है। अनुष्का ने ताइक्वांडो में लगातार प्रदर्शन करते हुए राज्य और क्षेत्रीय प्रतियोगिताओं से राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बनाई है। खांडवा में 9 से 13 सितंबर 2026 तक आयोजित 37वीं राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में 46-49 किलोग्राम वजन समूह में जीता गया कांस्य पदक उनकी खेल यात्रा की एक और उल्लेखनीय कड़ी है।

18 सितंबर को बक्सर पहुंचेगी राष्ट्रव्यापी स्वर्वेद संदेश यात्रा, नगर भवन में होगा भव्य आध्यात्मिक आयोजन

श्रद्धालुओं को मिलेगा आध्यात्मिक संदेश से जुड़ने का अवसर

बक्सर (संवाददाता)। संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज के पावन सान्निध्य में संचालित राष्ट्रव्यापी स्वर्वेद संदेश यात्रा 18 सितंबर को बक्सर पहुंचेगी। यात्रा के बक्सर पहुंचने के अवसर पर नगर भवन, बक्सर में शाम 6 बजे से भव्य आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में श्रद्धालुओं को आत्मिक चेतना, ध्यान-साधना और स्वर्वेद के दिव्य संदेश से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। आयोजन को लेकर स्थानीय स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं और श्रद्धालुओं में भी उत्साह देखा जा रहा है।

आयोजकों के अनुसार, राष्ट्रव्यापी स्वर्वेद संदेश यात्रा की शुरुआत 18 जुलाई को कन्याकुमारी, तमिलनाडु से हुई थी। यह यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत की आत्मिक चेतना को जागृत करने और जन-जन तक आध्यात्मिक संदेश पहुंचाने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। इसी क्रम में यात्रा विभिन्न स्थानों से होते हुए 18 सितंबर को बक्सर पहुंचेगी। बक्सर में आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से श्रद्धालुओं को स्वर्वेद के संदेश और ध्यान-साधना से परिचित कराने का प्रयास किया जाएगा।

कार्यक्रम में संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज द्वारा जय स्वर्वेद कथा प्रस्तुत की जाएगी। इसके साथ ही श्रद्धालुओं को ध्यान-साधना का अभ्यास भी कराया जाएगा। आयोजकों का कहना है कि ध्यान-साधना के माध्यम से लोगों को आत्मिक चेतना और आध्यात्मिक जीवन के संदेश से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। नगर भवन में होने वाले इस कार्यक्रम में श्रद्धालुओं के शामिल होने की तैयारी है। स्वर्वेद संदेश यात्रा को आयोजकों ने राष्ट्रव्यापी जनजागरण अभियान का हिस्सा बताया है। इस यात्रा के माध्यम से आध्यात्मिक चेतना का संदेश देश के विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। कन्याकुमारी से शुरू हुई यह यात्रा अब बक्सर पहुंचने वाली है, जहां आध्यात्मिक कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को स्वर्वेद के संदेश से जोड़ने का आयोजन किया गया है। बताया गया कि बक्सर में होने वाला यह कार्यक्रम आगामी 14 एवं 15 दिसंबर 2026 को स्वर्वेद महामंदिर धाम, उमरहां, वाराणसी में आयोजित होने वाले विहंगम योग संत-समाज के 103वें वार्षिकोत्सव एवं 25,000 कुण्डीय स्वर्वेद ज्ञान महायज्ञ के निमित्त चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी जनजागरण अभियान का महत्वपूर्ण चरण है। इसी अभियान के तहत स्वर्वेद संदेश यात्रा के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आयोजकों के अनुसार, अभियान का उद्देश्य जन-जन तक आत्मिक चेतना का संदेश पहुंचाना तथा स्वर्वेद जैसे दिव्य ज्ञानग्रंथ की ज्ञानधारा से लोगों को जोड़ना है। बक्सर में होने वाले कार्यक्रम को भी इसी उद्देश्य से जोड़ा गया है।

टुड़ीगंज स्टेशन के पास पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आए राजेश सिंह, पैर कटने से मौत

बक्सर (संवाददाता)। बक्सर-दानापुर रेलखंड पर टुड़ीगंज स्टेशन के समीप बुधवार की शाम पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे में व्यक्ति का एक पैर कट गया था और गंभीर रूप से रक्तस्त्राव हो रहा था। दुर्घटना के बाद मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी सूचना 112 पर दी। सूचना मिलने के बाद बचाव दल के चालक सोनल सिंह और मनोज कुमार मौके पर पहुंचे तथा घायल व्यक्ति को तत्काल डुमरांव अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि, अत्यधिक रक्तस्त्राव के कारण उनकी मौत हो गई।

मृतक की पहचान राजेश सिंह, उम्र करीब 40 वर्ष, पिता कपिल सिंह यादव, ग्राम बरूहां, थाना बगेन के रूप में हुई है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों और बचाव दल की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन गंभीर चोट और अधिक रक्तस्त्राव के कारण चिकित्सकीय प्रयासों के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी।

स्थानीय लोगों के अनुसार, राजेश सिंह अप लाइन पर ट्रेन की चपेट में आए थे। दुर्घटना में उनका एक पैर कट गया था और मौके पर ही काफी खून बह रहा था। हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग घटनास्थल पर जुट गए और घायल व्यक्ति को बचाने के लिए तत्काल सहायता की कोशिश की गई। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को भी दी।

बताया गया कि घटना बक्सर-दानापुर रेलखंड के टुड़ीगंज स्टेशन के समीप हुई। पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आने के बाद राजेश सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनकी स्थिति बेहद गंभीर होने के कारण स्थानीय लोगों ने बिना देर किए उन्हें अस्पताल पहुंचाने की पहल की। चालक सोनल सिंह और मनोज कुमार ने घायल को डुमरांव अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

वामन द्वादशी पर 23 सितंबर को निकलेगी भगवान वामन की भव्य रथ यात्रा, तैयारियों ने पकड़ी रफ्तार

बक्सर (संवाददाता)। वामन द्वादशी के अवसर पर भगवान वामन की प्रस्तावित रथ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। आयोजन को भव्य, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से वामन ग्लोबल फाउंडेशन की आयोजन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अब तक की तैयारियों की समीक्षा के साथ रथ यात्रा से संबंधित विभिन्न व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। समिति के सदस्यों ने अपनी-अपनी जिम्मेदारियों के तहत किए गए कार्यों की जानकारी दी तथा शेष तैयारियों को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने पर जोर दिया।

बैठक के दौरान रथ यात्रा के निर्धारित रूट, श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा एवं आवश्यक व्यवस्थाओं तथा महाप्रसाद वितरण को लेकर विशेष रूप से मंथन किया गया। आयोजन समिति ने कहा कि रथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को समय रहते अंतिम रूप दिया जा रहा है। साथ ही सभी सदस्यों से आपसी समन्वय बनाकर जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की अपील की गई।

भगवान वामन की रथ यात्रा 23 सितंबर को सुबह 8 बजे किला मैदान स्थित रामलीला मंच से प्रारंभ होगी। यहां से रथ यात्रा पुलिस चौकी, रामरेखा घाट, पी.पी. रोड, मुनीम चौक, यमुना चौक, ठठेरी बाजार मोड़, सब्जी मंडी मेन रोड, आदर्श नगर थाना, कॉलेज गेट मोड़ और जेल मोड़ होते हुए भगवान वामन मंदिर पहुंचेगी। आयोजन समिति की बैठक में निर्धारित रूट को लेकर भी विशेष चर्चा की गई। समिति की ओर से यात्रा मार्ग पर आवश्यक व्यवस्थाओं को समय रहते पूरा करने तथा श्रद्धालुओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखने की बात कही गई। रथ यात्रा के समापन के बाद श्रद्धालुओं के बीच महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। आयोजन समिति की ओर से शहरवासियों एवं श्रद्धालुओं से अधिक से अधिक संख्या में सपरिवार भगवान वामन की रथ यात्रा में शामिल होने की अपील की गई है। समिति का उद्देश्य वामन द्वादशी के अवसर पर आयोजित इस धार्मिक आयोजन को श्रद्धा, उत्साह और आपसी सहभागिता के साथ संपन्न कराना है। वामन ग्लोबल फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉ. राकेश राय (कल्लू राय) ने कहा कि वामन द्वादशी के अवसर पर आयोजित रथ यात्रा को लेकर फाउंडेशन के सभी सदस्य उत्साह के साथ तैयारियों में जुटे हैं।

नरबतपुर में सड़क निर्माण की राह हुई आसान, वर्षों पुरानी समस्या के समाधान की जगी उम्मीद

जल संसाधन विभाग की करीब 800 फीट जमीन का अधिकारियों ने किया स्थल निरीक्षण, अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद से स्थानीय लोगों में बढ़ा भरोसा

बक्सर (संवाददाता)।

नरबतपुर में ऐतिहासिक स्थल के पीछे रहने वाली बड़ी आबादी और प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए वर्षों से चली आ रही आवागमन की समस्या के समाधान की उम्मीद अब बढ़ गई है। कच्चे रास्ते और बारिश के दिनों में कीचड़ के कारण लोगों को होने वाली परेशानी को देखते हुए सड़क निर्माण की पहल तेज हुई है। नगर पंचायत की ओर से सड़क निर्माण का प्रस्ताव पहले ही लिया जा चुका है, लेकिन प्रस्तावित सड़क के मार्ग में जल संसाधन विभाग की जमीन आने के कारण निर्माण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही थी। अब जल संसाधन विभाग के अधिकारियों द्वारा स्थल निरीक्षण किए जाने के बाद इस बाधा के दूर होने और सड़क निर्माण का रास्ता साफ होने की उम्मीद जगी है।

जल संसाधन विभाग के अभियंता प्रमुख निखिल कुमार के निर्देश पर अधीक्षण अभियंता सुधीर कुमार बुधवार को अभियंताओं की टीम के साथ नरबतपुर पहुंचे। अधिकारियों की टीम ने मौके पर पहुंचकर गंगा पंप नहर के पास वर्षों से खाली पड़ी विभागीय भूमि का स्थल निरीक्षण किया। इस दौरान प्रस्तावित सड़क के मार्ग, विभागीय जमीन की स्थिति और सड़क निर्माण से जुड़े तकनीकी पहलुओं की जानकारी ली गई। बताया गया कि प्रस्तावित सड़क के रास्ते में करीब 800 फीट जमीन जल संसाधन विभाग की है। इसी जमीन के कारण सड़क निर्माण की प्रक्रिया में विभागीय अनुमति की आवश्यकता पड़ रही थी।

स्थल निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मौके की स्थिति को समझने के साथ संबंधित अभियंताओं और पदाधिकारियों से आवश्यक जानकारी प्राप्त की। प्रस्तावित सड़क किस स्थान से होकर गुजरेगी और विभागीय भूमि का कितना हिस्सा इसके मार्ग में आ रहा है, इस संबंध में भी जानकारी ली गई। अधिकारियों ने आगे की प्रक्रिया को लेकर संबंधित लोगों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद अब विभागीय स्तर पर सड़क निर्माण में आ रही तकनीकी और प्रशासनिक बाधा को दूर करने की प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद है।

विभागीय जमीन के कारण अटका था सड़क निर्माण: प्रस्तावित सड़क के मार्ग में जल संसाधन विभाग की जमीन आने के कारण नगर पंचायत के लिए निर्माण कार्य शुरू करना आसान नहीं था। विभागीय भूमि पर सड़क निर्माण के लिए जल संसाधन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी की आवश्यकता बताई जा रही है। ऐसे में अब विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौके का निरीक्षण किए जाने के बाद एनओसी की प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि सड़क निर्माण का वास्तविक कार्य अनुमति और अन्य आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद ही आगे बढ़ सकेगा।

बारिश में कच्चा रास्ता बन जाता है परेशानी का कारण: स्थानीय लोगों के अनुसार नरबतपुर के ऐतिहासिक स्थल के पीछे बड़ी संख्या में लोग निवास करते हैं। इसी क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय भी स्थित है। पक्की सड़क नहीं होने के कारण सामान्य दिनों में भी लोगों को आवागमन में परेशानी होती है, जबकि बारिश के मौसम में स्थिति और अधिक कठिन हो जाती है। कच्चा रास्ता बारिश के पानी के कारण कीचड़ से भर जाता है। ऐसे में पैदल चलने वाले लोगों के साथ स्कूली बच्चों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बारिश के दिनों में बच्चों के स्कूल आने-जाने में सबसे अधिक परेशानी होती है। कीचड़ भरे रास्ते के कारण बच्चों के कपड़े और जूते खराब होने के साथ रास्ते से गुजरना भी मुश्किल हो जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से इस मार्ग को पक्का कराने की मांग की जाती रही है। सड़क बनने से केवल स्थानीय आबादी को ही सुविधा नहीं मिलेगी, बल्कि प्राथमिक विद्यालय आने-जाने वाले बच्चों के लिए भी आवागमन काफी सुगम हो जाएगा। नगर पंचायत ने लिया था सड़क निर्माण का प्रस्ताव: स्थानीय स्तर पर समस्या के समाधान के लिए नगर पंचायत की ओर से सड़क निर्माण का प्रस्ताव लिया जा चुका है। प्रस्ताव सामने आने के बाद क्षेत्र के लोगों में उम्मीद जगी थी कि वर्षों से चली आ रही समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन प्रस्तावित मार्ग में जल संसाधन विभाग की जमीन आने के कारण निर्माण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही थी। इसके बाद विभागीय अनुमति प्राप्त करने के लिए मामले को संबंधित अधिकारियों के समक्ष रखा गया।

दिशा की बैठक में भी उठा था मामला: नरबतपुर में सड़क निर्माण की समस्या का मामला दिशा की बैठक में भी प्रमुखता से उठाया गया था। नगर पंचायत चेयरमैन प्रतिनिधि सह पूर्व जिला परिषद सदस्य डॉ. मनोज कुमार यादव ने बैठक में इस समस्या को अधिकारियों के समक्ष रखा था। उन्होंने प्रस्तावित सड़क के निर्माण में आ रही विभागीय जमीन की बाधा को दूर करने और आवश्यक प्रक्रिया पूरी कराने की मांग की थी।

दिशा की बैठक में मामला उठाए जाने के बाद जल संसाधन विभाग के अभियंता प्रमुख निखिल कुमार को पत्र भेजकर मामले में आवश्यक पहल करने का अनुरोध किया गया। इसके बाद अभियंता प्रमुख के निर्देश पर अधीक्षण अभियंता सुधीर कुमार ने अभियंताओं की टीम के साथ नरबतपुर पहुंचकर स्थल का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण को सड़क निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, क्योंकि इससे प्रस्तावित मार्ग में आने वाली विभागीय जमीन की वास्तविक स्थिति का मौके पर जायजा लिया गया।

अधिकारियों ने मौके पर ली जानकारी: निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने सड़क निर्माण के प्रस्तावित मार्ग और गंगा पंप नहर से संबंधित विभागीय जमीन का जायजा लिया। संबंधित अभियंताओं से जमीन और प्रस्तावित निर्माण से जुड़ी जानकारी प्राप्त की गई। इसके साथ ही आगे की प्रक्रिया के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए। विभागीय अधिकारियों के स्थल निरीक्षण के बाद अब स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और सड़क निर्माण में आ रही बाधा दूर हो सकेगी।

निरीक्षण के दौरान मौजूद रहे अधिकारी: स्थल निरीक्षण के दौरान डॉ. मनोज कुमार यादव, गंगा व सोन कैनाल के कार्यपालक अभियंता वीरेंद्र कुमार, नगर कार्यपालक अभियंता राजन कुमार, कनीय अभियंता दीनबंधु कुमार एवं नगर कनीय अभियंता प्रतीकधर सहित अन्य संबंधित लोग मौजूद रहे। अधिकारियों की मौजूदगी में प्रस्तावित सड़क के मार्ग और विभागीय जमीन से संबंधित स्थिति को समझा गया।

स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण के लिए यदि जल संसाधन विभाग की आवश्यक अनुमति और अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो वर्षों से चली आ रही समस्या के समाधान का रास्ता खुल सकता है। पक्की सड़क बनने से नरबतपुर के ऐतिहासिक स्थल के पीछे रहने वाली आबादी को आवागमन में सुविधा मिलेगी और प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को भी बारिश के दिनों में कीचड़ भरे रास्ते से गुजरने की परेशानी से राहत मिलने की उम्मीद है।

नरबतपुर की यह समस्या लंबे समय से स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। नगर पंचायत द्वारा सड़क निर्माण का प्रस्ताव लिए जाने के बाद भी विभागीय जमीन से जुड़ी अनुमति के कारण काम आगे नहीं बढ़ सका था। अब जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर स्थल निरीक्षण होने से प्रक्रिया में आगे बढ़ने की संभावना बनी है। हालांकि सड़क निर्माण के लिए आवश्यक विभागीय अनुमति और अन्य प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू हो सकेगा।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक मतिउर्रहमान द्वारा अजीमाबाद प्रिंटर्स, आर. सी. एफ./105, ग्राउण्ड फ्लोर, बी. एच. कॉलोनी, भूतनाथ रोड, कंकड़बाग, पटना- 800026 बिहार से मुद्रित एवं अमला टोली, मेन रोड़, बक्सर -802101, बिहार से प्रकाशित, संपादक- मतिउर्रहमान, E-mail:- qalamlok@gmail.com, Regn. No. BIHHIN/2017/72480